RESOLUTION REGARDING STARVATION DEATHS IN TRIBAL AREAS OF TRIPURA— Contd.

श्री विठ्ठलराव माधवराव जाधव (महाराष्ट्र) : उपसभाध्यक्ष महोदया हमारे सदन की माननीय सदस्या श्रीमती सरला माहेश्वरी जी ने 17 जुलाई, 1992 को उपस्थित किये गये निम्नलिखित संकल्प पर आगे विचार करने के लिये प्रस्ताव रखा है :

"यह सभा भुखमरी और भुख से संबंधित रोगों के कारण त्रिपुरा के आदिवासी क्षेत्रों में बड़ी संख्या में हुई मौतों, समाचार पत्रों की रिपोर्टों के अनुसार जिनकी संख्या 400 से भी अधिक है, पर अपनी गंभीर चिंता व्यक्त करती है और सरकार से आग्रह करती है कि वह स्थिति की गंभीरता को समझे और प्रभावित आदिवासी लोगों को तत्काल राहत पहुचाये और साथ साथ यह भी सुनिश्चित करे कि-

(i) इस समय सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मार्फत सप्लाई की जा रही वस्तुओं की मात्रा दुगुनी की जाये,

(ii) व्यापक स्तर पर ग्रामीण रोजगार योजनायें शुरू की जायें ; और

(iii) भुख से संबंधित रोगों से पीड़ित लोगों के इलाज के लिये पर्याप्त चिकित्सा-राहत उपाय शुरू किये जायें।'

उपसभाध्यक्ष महोदय, इसके बारे में मैं पिछली बार भी बोल चुका हूं। यह भी हमने स्पष्ट कर दिया है कि जो मौतें हुई हैं वह भुखमरी से नहीं हुई । फिर भी गैस्ट्राएंट्राइटिस जो बीमारी है उसकी वजह से कुछ मौत हुई है । आप जानते हैं कि यह जो उत्तर पूर्वी भाग है, उसमें त्रिपुरा भी आता है । जो कहते हैं–सात भगिनी Seven Sisters और वह निसर्ग से बहुत ही सुन्दर इलाका है । फिर भी निसर्ग का बहुत ही वरदान है । मगर मानवीय वरदान वहा बहुत कम है। त्रिपुरा, नागालैंड, मणिपुर मिजोरम मेघालय और आसाम छोटे-छोटे राज्य हैं । उनका विकास होना चाहिये और वहां एक बहुत बड़ी निसर्ग की संपत्ति है । यदि वहा के नैच्युरल रिसोर्सिज के बेसिस पर उसका विकास करने के सरकार प्रयास करेगी तो मुझे लगता है कि यह हमारे देश को काफी मात्रा में मुद्रा भी दे सकती है । इतना उस पर पुटेंशल है । फिर भी बात ऐसी है कि इस दृष्टि से सोचना मैं जरूरी समझता हूं ।

उपसभाध्यक्ष महोदय, इसमें तो कोई दो राय नहीं कि इंसान की जो बुनियादी जरूरतें हैं– रोटी कपड़ा और मकान वह तो मिलनी ही चाहिये । जो संविधान बनाया पंडित जवाहर लाल नेहरू के नेतृत्व में, डा० बाबा साहेब अम्बडकर ने यह तीन चीजें तो सारे हिन्दुस्तान की जनता को दी है । रोटी कपड़ा, मकान, शिक्षा और एम्प्लोयमेंट यह तो देना हमारा नैतिक कर्तव्य है । मगर बातें कुछ ऐसी हैं कि सात योजनायें हमने बनाई हैं । सात योजनाओं में लाखों करोड़ों रुपये खर्च किये हैं फिर भी हमारी समस्या अभी बहुत बड़ी है । Much More greater things तो उसके लिये हमारी सरकार निरन्तर प्रयास कर रही है । मैं यह नहीं कहता कि जो भी बीच में थोड़े-थोड़े समय के लिये विपक्ष की सरकारें, आई, उसका परिणाम भारत की जनता पर यह हुआ कि उन्होंने सारा इकनोमिक बैलेंस जो था आर्थिक तराजू जो था, वह डिस्टर्ब कर दिया । **(व्यवधान)**

श्री सत्य प्रकाश मालवीय (उत्तर प्रदेश) : तीन साल में गिरावट हो गई ? 45 साल की कांग्रेसी हुकूमत में तो नहीं हुई, 3 साल में हो गई ।

श्री विठ्ठलराव माधवराव जाधव : गिरावट के लिये एक दिन भी काफी होता है ।

एक माननीय सदस्य : जैसे घोटाले आज हो रहे हैं, ऐसे तो नहीं हुये ।

श्री विट्ठलराव माधवराव जाधव : इमारत बनाने में बहुत दिन लगते हैं लेकिन गिराने में ज्यादा देर नहीं लगती ।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGESH DESAI) : Please no question answer.

श्री संघ प्रिय गौतम (उत्तर प्रदेश): जाधव साहब, आपकी सरकार नहीं, आपकी पार्टी की सरकार है ।

श्री विट्ठलराव माधवराव जाधव : अभी तो हमारी पार्टी की सरकार है । हम सिर्फ इतना ही कहेंगे कि:–

एक उल्लू ही काफी है बर्बाद
गुलिस्तां करने के लिये,

हर शाख पे उल्लू बैठा है,
अंजामे गुलिस्तां क्या होगा ।।

श्री संघ प्रिय गौतम : नही होगा जो हो रहा है आपके यहां ।

श्री विट्ठलराव माधवराव जाधव : वही होगा जो अंजाम-ए-खुदा होगा । यह अपने आप टूट गये, हमने तो नहीं गिराया आपको । यह आपकी हमेशा से नीति रही है कि आप जब भी सत्ता में आते हैं तो दूसरों की बजाय, आपस में बहुत भारी संख्या में झगड़ते हैं और फिर भारत की जनता आपको बाजू में बिठा देती है । मैं इसके विस्तार में नहीं जाना चाहता, लेकिन यह जो उत्तर-पूर्व भाग है–त्रिपुरा, त्रिपुरा के बारे में हमारी महिला भगिनी ने एक प्रस्ताव रखा है, इसका विकास तो जरूर होना चाहिये मगर यह जो राजनीति से प्रेरित है कि भूखमरी की वजह से मौतें हुई हैं, इसको मैं मंजूर नहीं करूंगा ।

उपसभाध्यक्ष महोदय, पहले ही काफी वक्ताओं ने बयान किया है कि काफी मात्रा में वहां अन्न-धान जा रहा है । वहां पब्लिक डिस्ट्रिब्यूसन सिस्टम को इफेक्टिव करने का प्रयास हो रहा है । बड़ी मात्रा में वहां अनाज भी जा रहा है, मगर बात ऐसी है कि प्रदेश छोटा है और लोग जो हैं वे आदिवासी हैं, ट्राइबल हैं, अविकसित हैं और उसका फायदा उठाकर जो अन्दर काम करने वाले दलाल हैं वे लोग राइस वगैरह बंगला देश में स्मगल करके भेज देते हैं । तो यह सबसे बड़ी बीमारी है करप्शन की । वहां जो जनता के लिये अनाज सरकार भेजती है, दूसरी कोई जरूरी चीजें भेजती है, मगर जिसके लिये वह भेजती है, उस तक पहुंचाने में बहुत दिक्कतें आती ह । इसके बारे में गंभीरता से सोचना मैं बहुत जरूरी समझता हूं ।

उपसभाध्यक्ष महोदय, शायद आप भी तो स्वतंत्रता आंदोलन से आये हुये हैं मेरे ज्येष्ठ बंधु-भाई के समान हैं । गांधी जी ने कहा था एक दिन कि "अगर ईश्वर मुझे पुनः जन्म देगा तो मैं कहूंगा कि रोटी के रूप में दे, जिसको खाकर गरीब अपनी भूख मिटा सके ।" तो सबसे बड़ा जो इंसान की कमजोरी है, वह रोटी है । इसलिये रोटी देना जरूरी है । हमारे देश में प्रयास हुआ है कांग्रेस की सरकार द्वारा और जिस प्रदेश महाराष्ट्र से मैं आता हूं, मुझे अच्छी तरह याद है कि 1972 में जो अकाल आया था उस वक्त हमारे मुख्य मंत्री मंत्री स्वर्गीय वसन्तराव नाइक साहब ने कहा था कि "1972 में महाराष्ट्र में इतना बड़ा अकाल आया था कि इस सेंच्युरी में इतना बड़ा अकाल कभी नहीं आया, मगर महाराष्ट्र में एक भी आदमी बिना रोटी के नहीं मरेगा ।" उन्होंने वह प्रयास किया और बहुत ही इफेक्टिव तरीके उन्होंने वह काम पूरा किया । हमने रोजगार गारंटी स्कीम शुरू की महाराष्ट्र में, अभी राष्ट्रीय स्तर पर उसको स्वीकार किया गया है –राष्ट्रीय रोजगार योजना को, और महाराष्ट्र में इस स्कीम के अंदर इतने काम हुए– सर-क्यूलेशन टैंक्स बने हैं, वाटर सप्लाई वर्क्स बने हैं–और काफी समस्यायें प्रदेश की हल करने में हमारी वह रोजगार गारंटी योजना सफल रही है । मैं आग्रह करता हूं केन्द्र सरकार से, जो हमारे केन्द्र के

[श्री संघ प्रिय गौतम]

मंत्री, माननीय कृषि मंत्री जी बैठे हैं जैसे मैंने पहले भी कहा था कि यह हमारे देश का गौरव है कि जिस मनुष्य को जिस नेता को कृषि का ज्ञान है, आज वही कृषि मंत्री है, जाखड़ साहब, और वह प्रयास कर रहे हैं कि निरन्तर कि हमारे देश में कृषि की उपज कैसे बढ़े । सही बात तो यह है कि चाहे त्रिपुरा की बात हो, चाहे मेघालय की बात हो या मिजोरम की बात हो, जो हमारे देश में नैसर्गिक संपदा है या वन संपत्ति की बात हो या और कोई बात हो या एनिमल हसबण्डरी की बात हो, उसके लिए प्रयास करने की जरूरत है । अगर हम इस दृष्टि से प्रयास करें तो मुझ ऐसा लगता है कि त्रिपुरा की समस्या या और भी छोट-छोट प्रांतों की समस्या बहुत अच्छे तरीके से हल हो सकती है । इसीलिए मेरा सरकार से अनुरोध है, जैसा माननीया सरला माहेश्वरी जी ने कहा है कि व्यापक स्तर पर ग्रामीण रोजगार योजना शुरू की जाए, इसका मैं बिल्कुल समर्थन करता हूं कि ग्रामीण रतजगार योजना का शुरू होना बहुत जरूरी है ।

महोदय, त्रिपुरा एक आदिवासी क्षेत्र है। आदिवासी लोगों के जीवन, आदिवासी लोगों की जो पुरानी संस्कृति है उसकी रक्षा करते हुए हम उन्हें बढ़ावा दे सकते हैं। तो इस प्रकार की योजना शुरू करना बहुत जरूरी है ।

उपसभाध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं कि आदिवासी लोग जो काम करते हैं, हैं जो भी वस्तुएं तैयार करते हैं, उनकी सारी दुनियां में मांग है । अगर उनको बढ़ावा दिया जाए, उनके लिए एक अच्छी तरह से योजना बनाई जाए तो मैं समझता हूं कि . . .

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGESH DESAI) : The resolution will lapse after this House Session and today is the last day for this business because the House will not sit on 14th August. So if you want to have the reply of the Minister so that some concrete steps can be taken· I would request the Members to be brief and and give enough time for the Minister to reply.

श्री विठ्ठलराव माधवराव जाधव : ठीक है, मैं प्रयास करूंगा बहुत कम समय में समाप्त कर सकूं, लेकिन इसके पहले मैं बहुत जरूरी मानता हूं कि इस ग्रामीण रोजगार व्यवस्था के बारे में हमारी माननीय सदस्य ने जो बात उठाई है, वह बहुत जरूरी चीज है और मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि जैसे महाराष्ट्र में रोजगार-गामी योजना शुरू करके वहां के ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को, आदिवासी क्षेत्र के लोगों को, हरिजन-गिरिजन लोगों को रोजगार देने का प्रयास महाराष्ट्र सरकार ने किया है, उसी प्रकार का प्रयास सारे देश में होना चाहिए और जो इकोनोमिकली बैकवर्ड हैं, आर्थिक दृष्टि से बहुत दुर्बल हैं, जहां अनुसूचित जाति/जनजाति के लोग रहते हैं वहां ऐसी रोजगार की योजना बनाकर उनको बहुत प्रबल बनाने की जरूरत है। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि यह जो सात उत्तर-पूर्व के सात राज्य हैं, उनमें बहुत ही इंटेंसिव एम्पलायमेंट गारन्टी स्कीम शुरू करके आदिवासी लोगों को अगर रोजगार देने का प्रयास करेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि उनके जीवन में जरूर अच्छे दिन आएंगे और बहुत सारी आदिवासी पापुलेशन पुअरटी लाईन के ऊपर आ सकती है ।

उपसभाध्यक्ष महोदय, दूसरा महत्वपूर्ण सवाल यह है कि हमारी माननीय सदस्या ने कहा कि चार सौ लोग मरे हैं । ये लोग गेस्ट्रोटी से मरे हैं या कोलरा से मरे हैं, बीमारी जो है ऐसा नहीं है कि अमीर को एक बीमारी हो और गरीब को एक, बीमारी तो सबको आती है, लेकिन मूलभूत सुविधा अगर उपलब्ध न हो, पीने का स्वच्छ पानी न हो, खाने का अनाज अच्छा न हो, समय पर आरोग्य सुविधा न मिले तो हो सकता है कि बीमारी से, कई तरह की बीमारी से लोग मर सकते हैं। तो यह बहुत जरूरी है कि ग्रामीण क्षेत्र में आरोग्य की व्यवस्था की जाए । जैसा कि त्रिपुरा में या महाराष्ट्र के आदिवासी इलाकों में कई जगह गेंस्ट्रटी या अन्य बीमारी से मरे हैं तो इस दृष्टि से यह जो आम सवाल है, यह खाली त्रिपुरा या और जो अविकसित क्षेत्र हैं उसका सवाल नहीं है जो प्रगत क्षेत्र हैं वहां भी हो सकता है ।

गेस्ट्रेटी, कोलरा कलकत्ता, बंबई और दिल्ली में भी हो सकता है। यह जो बड़ी बड़ी बीमारी हैं, उनका पूरी तरह से निवारण करना हमारा प्रमुख कर्त्तव्य बनता है। इस दृष्टि से सरकार को कुछ योजना बनानी चाहिए।

उपसभाध्यक्ष महोदय, सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मैं समझता हूं, वह यह है कि अगर हमें ग्रामीण क्षेत्र का विकास करना है तो सिर्फ दो ही बातें देखनी हैं--कृषि तथा ग्रामीण औद्योगीकरण, क्योंकि हमारे देश की जो नीति है या अर्थनीति है, यह एग्रो बेस्ड इकोनोमी है, इंडस्ट्रियल बेस्ड नहीं है। हमारे देश में उद्योग-धंधे बहुत कम हैं और उसको बनने के लिए भी काफी समय लगने वाला है, मगर जो खेती है, हमारे देश में जिसमें अनाज पैदा होता है, कृषि योग्य जो जमीन है बहुत बड़े पैमाने पर हमारे देश का जो क्लाइमेट है, वातावरण है, यह सारा क्रोप्स के लिए बहुत अच्छा है। ग्रेन से लेकर ज्वार तक या बाजरा तक या काटन तक या अन्य फलों के उत्पादन के लिए और इस दृष्टि से कृषि के मामले में अनुसंधान तो बहुत हो रहे हैं हमारे देश में लेकिन जो भी अनुसंधान हो रहे हैं उनका सही जगह तक पहुंचाना बहुत जरूरी है। जिस खेत में उसके जाने की जरूरत है जब तक वह वहां नहीं पहुंचेगा, लेबोरेट्री तक ही सीमित रहेगा तो उस अनुसंधान का कोई मतलब नहीं होगा। इसलिए मेरा केन्द्रीय सरकार से अनुरोध है कि ये जो इलाके हैं, ये उत्तर-पूर्व के इलाके, जहां कृषि बहुत अच्छी है, जहां बहुत सा पानी है और अन्य सुविधायें उपलब्ध हैं, वहां कृषि को और बढ़ावा देना बहुत जरूरी है। तो कृषि को बढ़ावा देने के लिए हमारी जो कृषि नीति है, मैंने पहले भी कई दफा कहा था और मान्यवर मंत्री जी ने भी बताया है कि हमारी एक नयी कृषि नीति तैयार की गई है, उसका ब्लूप्रिंट तैयार है, वह उसे कब सामने रखेंगे? मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि वे जल्दी से जल्दी हमारे देश की कृषि नीति सामने रखें और हमारे देश के लाखों-करोड़ों किसानों को राहत दी जाए।

उपसभाध्यक्ष महोदय, एक आखिरी बात कहकर मैं अपना भाषण समाप्त करूंगा और वह यह है कि इन एरियाज में स्मगलिंग बहुत होती है। बंगला देश के साथ जो हमारा बार्डर है या पाकिस्तान के साथ जो बार्डर है या चीन के साथ जो बार्डर है या नेपाल के साथ जो बार्डर है, तथा और जो भी बार्डर के स्टेट्स हैं, वहां स्मगलिंग बड़े पमाने पर होती है। उधर से माल इधर आता है, इधर से उधर जाता है। खुले तरीके से आता है। मुझे भी एक दफा सौभाग्य प्राप्त हुआ, मैं नागालैण्ड गया था, मणिपुर गया था तो मैंने देखा कि वहां फारेन गुड्स फ्रीली मार्केट में मिलती हैं, कोई आपत्ति नहीं होती और हमारे यहां से अनाज खुले तरीके से जाता है। यह मैंने अपनी आखों से देखा है। इसके लिए कोई व्यवस्था जरूर होनी चाहिए और सरकार इस बारे में गंभीरता से सोचे और सही बात तो यह है कि लोगों के भुखमरी से, बीमारी से मरने का कारण यह है कि हमारे देश में भ्रष्टाचार इतने बड़े पैमाने पर है कि कोई भी चीज जो गरीबों के लिए दी जाती है वह उन तक पहुंचती नहीं। बीच में जो दलाल बैठे हैं, बिचौलिए बैठे हैं, वह गरीबों तक वस्तुयें पहुंचाने नहीं देते वह सारी क्रीम ले लेते हैं। गरीबों तक छाछ तक पहुंचने नहीं देते यह सबसे बड़ी समस्या है इस समस्या को हल करने के लिए हम सबको राजनीतिक विचारधारा से ऊपर उठकर मिलकर यह तय करना है कि हमें इस देश से भ्रष्टाचार, करप्शन, स्मगलिंग माल प्रक्टिसेज को खत्म करना है। इसके लिए हमें कांग्रेस पार्टी, बी.जे.पी. कम्युनिस्ट के रूप में नहीं बल्कि मानवता के नाते भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ना है और यह हम सबका पवित्र कर्तव्य है। इस दृष्टि से मैं अनुरोध करता हूं कि त्रिपुरा की जो समस्या है, जो माननीय सदस्या ने अपने संकल्प में सामने रखी है मैं उसका समर्थन तो जरूर करता हूं लेकिन जो भी कुछ इसमें गलत बातें आई हैं, वह बातें वे छोड़ दें और अपना प्रस्ताव वापस ले लें। त्रिपुरा के विकास के बारे में जो करना है, केन्द्रीय

[श्री विठ्ठलराव माधव राव जाधव]

सरकार उसका पूरा ध्यान रखे। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

*SHRI SARADA MOHANTY (Orissa) : Mr. Vice-Chairman Sir, I rise to support whole-heartedly the Resolution moved by Shrimati Sarala Maheshwari expressing serious oncern over the large number of leaths in the tribal areas of Tripura lue to starvation and hunger related liseases. This is a very important Resolution. During her speech, when Shrimati Maheshwari was narrating the pitable condition of the tribles in Tripura due to starvation, I was reminded of the great famine of 1872 that affected Orissa, Bihar and Bengal. This famine is called "The Nanka Durvikhya" in Orissa. Although I have not seen the misery of the affected people with the own eyes, I have heared about their plight from my ancestors. I have read about the heart-rending narration of the miserable condition of the people during the 1872 famine from many books. I cannot forget the description in the books about a mother disallowing her son to share the food with her.

Mr. Vice-Chairman Sir, during that period there was not proper and efficient means of transportation. But still, the then British Government tried its best to control the situation. Today we are self-sufficient in food grains. Now we can transport commodities from place to place very easily. In this context deaths due to starvation and hunger-related diseases are really a matter of shame and sorrow for us. The people in the affected areas do not hesitate to eat whatever food they get irrespective of its nutritious value. As a result they suffer from various diseases and mal-nutrition. This is exactly what has happened with the poor tribals of Tripura. The hungry parents do not hesitate to sell away their children for a few rupees.

*English translation of the original speech delivered in Oriya.

Mr. Vice-Chairman Sir, many of my colleagues have either blamed the Central Government or the State Government for this problem I am very sorry to say that nobody has given any concrete suggestion for solving this problem. In my opinion the government irrespective of which party is in power, should ensure that no citizen dies of starvation in the country.

A friend of mine during the course of his speech spoke about the reported starvation deaths in Koraput district of Orissa. I want to tell it emphatically that the allegation is untrue. It is true that many tribals of Koraput suffered from diarrhoea. The honourable Chief Minister of Orissa took prompt action on war-footing to save the life of the tribals. The doctors of all the three medical colleges of the state were sent to the affected areas. Steps were taken by the State Government to send medicines, food grains and other essential commodities to the affected people. I request both the Central and the State Governments to take immediate steps to save the valuable lives of the tribals in Tripura. If there is any pilferage of the relief material, government should take stern action against the guilty. The Government should check the smuggling of relief materials to Bangladesh

Before concluding I would like to say a few words about the plight of the domestic animals of the affected people. The Government should ensure the supply of foddier to the affected areas of Tripura for the consumption of the domestc animals. The tribals take the help of cows and buffalos for agriculture.

I hope both the Central and State Governments will take steps to save the life of the tribals in Tripura.

Thank you.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGESH DESAI) : Now, Mr. Sudhir Ranjan Majumdar. This is his maiden speech.

SHRI SUDHIR RANJAN MAJUMDAR (Tripura) : Mr. Vice-Chairman, Sir, the Resolution moved by Mrs. Sarala Maheshwari is not out of any good intention, I should say. It is politically motivated. The honourable Members have been observing for a long time that since the present Government, the Pradesh Sarkar, came to power there, the Marxists have been continuously making this propaganda against the Government and trying to create some misunderstanding about the administration there and trying to create some dissension whereby the harmony between the communities, tribal and non-tribal, is disturbed so that they can make something out of this disturbed situation and can reap some political milcage out of this false propaganda against the Government, Sir, the Congress Government in Tripura have been trying to improve the condition of the tribal people and to bring them into the mainstream with utmost sincerity because these tribal people are very poor people and the means of livelihood are not available to them. To bring all these facilities and to improve their economic condition, we have taken up many schemes. I should say because I was the Chief Minister, and I myself initiated many schemes, and I can put these things before the House. And if you compare the Marxist rule for ten years in Tripura and this four years and a few months' rule of the Congress, you will find that there is a great difference in implementing sincerely the schemes that have been taken up by the Central Government under the leadership of Smt. Indira Gandhi, Shri Rajiv Gandhi, and now our Prime Minister, Shri Narasimharao. The entire effort is now devoted for the development of the lot of these tribal people during the Congress rule. Then, Sir, many schemes were taken up, and the Government of India had given huge funds to the then Left Front Government. Sir, we have seen it because I was then the Opposition leader. Sir, those funds were misused. Those funds were not utilised for the purpose for which they were given. They were cleverly diverted and as a result the tribal people were deprived of many good things. They were alienated. They were exposed to terrorism and insurgency. This was created by them. This Marxist party has formed an organisation, an insurgent outfit called ATTF. They are creating disturbances. They are killing tribal people and are creating a situation of insecurity. As a result many good programmes could not be implemented in those remote areas. Now they are using this august House not for any good intention but for propaganda to create an impression in the minds of the tribal people that they are sympathetic to them so that these tribal people may turn against the present Congress Government there and a situation of insurgency may be created. It is with that objective in view that this Resolution has been brought before us and we cannot support it. It is because their intention behind it is not good. And now they want to show all sympathy for the tribal people. I want to ask one question here. When they were in power, what were the good scheme that they had taken up ? For ten years they were a ruling party. What did they do ? They do not know about the modern techniques in cultivation, They are only accustomed to jhuming cultivation and nothing has been done by them in that regard.

3.00 P.M.

We have taken up new schemes. First of all, a vegetable pockets scheme has been taken up with the help of the Central Government and this scheme is being implemented in that State with sincerity. As

[Shri Sudhir Ranjan Majumdar]

a result, we are getting some encouragement for adopting modern techniques in agriculture. The Government has laid much stress on rubber gardens and on horticulture because three-fourth of the area is hilly where plain land cultivation is not possible. Therefore, the Government has taken up all these schemes and these are being implemented.

In Tripura, tribal population constitute 29 per cent of the total population. The Government is now spending more than 60 per cent of the total money for general development of tribal people. But what happened in the earlier days ? Only 40 per cent was being spent. And now they are tring to show so much of sympathy for the tribal people, Whatever amount was allocated and whatever scemes were formulated for the development of tribal areas did not benefit the tribal people, because those schemes were not implemented although money was spent.

The Resolution says that 400 tribals died of starvation. I should say this is an untrue statement. Not a single person died of starvation. It is a false propaganda; it is disinformation with a bad motive behind it. There is some motive behind this. That is why it has been brought forward. I want to warn them. They should stop this propaganda, this disinformation. Otherwise this would result in disturbance and disharmony among the people.

SHRI SUNIL BASU RAY (West Bengal) : How ? (*Interruptions*)

SHRI SUDHIR RANJAN MAJUMDAR : You should be sincere in your efforts. But you are not sincere, I should say. This is not a sincere Resolution.

SHRI SATYA PRAKASH MALAVIYA : What about the demands made in the Resolution ?

SHRI SANGH PRIYA GAUTAM : The demands are very clear.

SHRI SATYA PRAKASH MALAVIYA : The demands are spelt out in the Resolution.

SHRI SANGH PRIYA GAUTAM : We are concerned over it. We need not go into the reasons. After all People have died. (*Interruptions*).

SHRI SUDHIR RANJAN MAJUMDAR : Not a single tribal died of starvation. This is a false propaganda. (*Interruptions*) Some people have died. It is not 400. But ...

SHRI SANGH PRIYA GAUTAM : But the fact remains that people have died.

SHRI SUDHIR RANJAN MAJUMDAR : The number is not more than 10. These were due to gasteroenteritis epidemic. But it was arrested because of the steps taken by the State Government because of the timely action taken by the State Government. (*Interruptions*).

SHRI SHIV CHARAN SINGH (Rajasthan) : You should say whether it is true or not. That is all.

THE VICE-CHAIRMAN ((SHRI JAGESH DESAI) : Let us understand that this is his maiden speech. Please do not interrupt him.

SHRI SANGH PRIYA GAUTAM : But Sir, he has been the Chief Minister.

SHRI SHIV CHARAN SINGH: That is why he is 'ex'

SHRI SUDHIR RANJAN MAJUMDAR : Why do I oppose this Resolution ? It is because it is politically motivated. But I do not say that there is no necessity fo

sending immediate relief. It is necessary. I am confident that with the steps taken by the State Government with the help of the Government of India, this would be solved. I am quite confident. Sir, in Tripura...

PROF. SAURIN BHATTACHARYA (West Bengal) : Sir, I am on a point of order.

THE VICE-CHAIRMAN: (SHRI JAGESH DESAI) Why do you want to interrupt him.

PROF. SAURIN BHATTACHARYA : Will you yield for a minute, Mr. Majumdar ?

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGESH DESAI) : This is his maiden speech, Mr. Bhattacharya. (*Interruptions*).

PROF. SAURIN BHATTACHARYA : It is not to interrupt him. Just one point. So far as the Resolution goes, if there is any imputation of motives to a particular Government, the question of political motives might arise. Otherwise, from his intimate knowledge of Tripura, undoubtedly, as the Chief Minister once of that State, he can throw much light on the exact situation obtaining in Tripura.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGESH DESAI) : That is what he is doing.

PROF. SAURIN BHATTACHARYA : But in this Resolution, there is nothing political. First, he said that there was not a single death. Later on, he said that there were some deaths due to some epidemic, but it was arrested.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGESH DESAI) : Mr. Majumdar, you carry on.

PROF. SAURIN BHATTACHARYA : I am thankful to you, Sir.

SHRI SUDHIR RANJAN MAJUMDAR : In the end, I would urge upon the Central Government to strengthen the efforts of the State Government by providing all possible help so that the State Government can implement all these schemes, which have, at present, been taken up. I am sure, with the implementation of these schemes, the State would be developed and the lot of the tribal people would also improve. I am sure, the State Government would be able to face the situation. Thank you.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGESH DESAI) : Shri Hanumantha Rao. He is not here. Shri Satya Prakash Malaviya.

श्री सत्य प्रकाश मालवीय : माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, श्रीमती सरला माहेश्वरी जी के प्रस्ताव में त्रिपुरा के आदिवासी लोगों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए जो मांग रखी गई है कि इस समय सार्वजनिक वितरण प्रणाली में ... (**व्यवधान**)

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGESH DESAI) : Just one minute, I enquired from the Minister as to how much time he will take for intervention. He says, half an hour. If you are interested to hear the Minister, I think we can close the discussion at 4.30 p.m. It is for the House to agree, I cannot force.

SOME HON. MEMBERS : Yes.

श्री सत्य प्रकाश मालवीय : मैं यह निवेदन कर रहा था कि श्रीमती सरला माहेश्वरी के प्रस्ताव में त्रिपुरा के आदिवासी लोगों को राहत पहुंचाने के लिए तीन मांगे रखी गई हैं। एक तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली की मार्फत सप्लाई की जा रही वस्तुओं की मात्रा दुगुनी की जाए, दूसरी व्यापक स्तर पर ग्रामीण रोजगार योजनायें शुरू की जाय और तीसरी भूख से संबंधित रोगों से पीड़ित

[श्री सत्य प्रकाश मालवीय]

लोगों के इलाज के लिए पर्याप्त चिकित्सा राहत उपाय शुरू किये जाय। मेरे मित्र श्री मजूमदार जो मुख्य मंत्री भी रहे हैं, बोल रहे थे और उन्होंने पूरे प्रस्ताव का विरोध किया है। इससे मैं यह समझ पाया हूं कि जो श्रीमती सरला माहेश्वरी ने नौन मांगें रखी हैं राहत कार्यों के लिए, इनका भी श्री मजूमदार ने विरोध किया है। मांग में कहीं यह नहीं कहा गया है कि कोई आदमी भुखमरी से मरा, भूख से संबंधित रोगों से कहा है। इसकी चर्चा मैं इसलिए कर रहा हूं कि श्री मजूमदार जब मुख्य मंत्री थे तो उस वक्त चर्चा थी कि त्रिपुरा में आदिवासी क्षेत्रों में कुछ लोगों की मौतें भूख से हुई हैं (**व्यवधान**)

श्री सुन्दर सिंह भंडारी (राजस्थान): बोल कर चले गये।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय: बैठे हैं।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGESH DESAI) : He is very much sitting in the House.

श्री सत्य प्रकाश मालवीय: उनका कहना था कि :—

"There has not been a single case of death due to starvation,' says Mr. Sudhir Ranjan Majumdar, but he admits that a few deaths have been caused by an outrage of gastroenteritis which has now been arrested.

So, at that time, when he was the Chief Minister, he had admitted that certain deaths did occur there but they were not on account of starvation but gastroenteritis. गेस्ट्रोइंटराइटिस एक ऐसा मर्ज है जो पेट की बीमारी के कारण होता है। जब मनुष्य को आवश्यकतानुसार भोजन नहीं मिलता है या पौष्टिक आहार नहीं मिलता है तो वह मनुष्य बीमार पड़ जाता है। पौष्टिक आहार न मिलने के कारण धीरे-धीरे उसकी मृत्यु हो जाती है। मैं समझता हूं कि कम से कम जो मांग श्रीमती सरला माहेश्वरी जी ने रखी है, उस मांग का समर्थन तो करना ही चाहिए था। जब भूतपूर्व मुख्य मंत्री उनकी मांग का समर्थन नहीं करेंगे तो डा० जाखड़ जो केन्द्रीय सरकार के मंत्री हैं या जो प्रधान मंत्री हैं ...(**व्यवधान**)

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGESH DESAI) : He has said that the Central Government must give us funds.

SHRI SANGH PRIYA GAUTAM : But he should say that the State Government should release that fund.

SHRI SATYA PRAKASH MALAVIYA : But he has opposed the Resolution in toto. That is my contention.

उसी वक्त यहां भी चर्चा हुई थी, मैं उसको स्मरण कराना चाहता हूं कि यह लोग राशन कार्ड बेच रहे हैं। इसलिए राशन कार्ड बेच रहे हैं क्योंकि उनके पास राशन कार्ड के ज़रिये से मिलने वाली चीज़ों को खरीदने की शक्ति नहीं है। इसलिए राशन कार्ड बेचे गए। यह भी खबरें आईं कि लोगों ने अपने बच्चों को बेचा। यह भी खबरें आईं कि उनकी झोंपड़ी की टीन की छत को भी बेचा। यह भी खबरें आईं कि कम से कम 1000—1200 ...(**व्यवधान**)

SHRI SUDHIR RANJAN MAJUMDAR : On a point of order.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGESH DESAI) : On a point of information.

SHRI SUDHIR RANJAN MAJUMDAR : These starvation deaths and selling of ration cards are all newspapers reports.

SHRI SATYA PRAKASH MALAVIYA : I have said that these are newspaper reports.

SHRI SUDHIR RANJAN MAJUMDAR : These are not true.

श्री सत्य प्रकाश मालवीय : मैं सिर्फ यह कह रहा था कि यह खबरें आईं। उन खबरों में यह भी है कि काफी लोग रोजगार की तलाश में वहां से बंगलादेश की ओर चले गए, मिजोरम जो अपने देश का एक हिस्सा है, वहां चले गये। लेकिन त्रिपुरा की जो स्थिति है, वह बहुत चिंतनीय, दयनीय और गम्भीर है। वहां के आदिवासी इलाकों में रहने वाले जो लोग हैं वह बहुत ही नारकीय जीवन जी रहे हैं। इस स्थिति को सुधारने के लिए हम सब लोगों को प्रयास करना चाहिए। एक छोटा सा राज्य है। वहां की आबादी 28 लाख की है और मुझे यह कहते हुए बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि वहां का लिटरेसी रेट काफी अच्छा है। 1991 के सेंसस के अनुसार वहां का लिटरेसी रेट 60.39 परसेंट है। महिलाओं का लिटरेसी रेट 50.1 प्रतिशत है और पुरुषों का 70.8के प्रतिशत है। इतना अच्छा लिटरेसी रेट है और छोटा सा राज्य है लेकिन वहां पर चर्चायें होती हैं कि लोग भुखमरी से मर रहे हैं। मैं इस बात को मानता हूं कि हो सकता है कि भुखमरी से मौत न भी हुई हो, मुझे वस्तुस्थिति की जानकारी नहीं है लेकिन कम से कम जैसे मैंने कहा कि जब आदमी को खाना नहीं मिलेगा, दवा नहीं मिलेगी, आदमी बीमार पड़ेगा तो चिकित्सा नहीं होगी, पौष्टिक आहार नहीं मिलेगा। तो धीरे-धीरे रोगों से लड़ने की उनकी शक्ति समाप्त हो जाएगी और उनकी मौत हो जाएगी। इसलिए अंततोगत्वा भूख से ही मौत होगी। इसलिए मैं सिर्फ यह निवेदन करना चाहता हूं, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, कि केन्द्र सरकार की भी इस संबंध में काफी जिम्मेदारी है। हमारे संविधान निर्माताओं ने संविधान बनाया था तो निदेशक सिद्धांत का जो अनुच्छेद 47 है मैं इस बात को जानता हूं कि वह बाईंडिंग नहीं है लेकिन निदेशक सिद्धांत का मतलब यह है कि केन्द्र सरकार को इस मामले में आगे आना चाहिए। अनुच्छेद 47 में कहा गया है :

"DUTY OF THE STATE TO RAISE THE LEVEL OF NUTRITION AND THE STANDARD O F LIVING AND TO IMPROV E PUBLIC HEALTH—

The State shall regard the raising of the level of nutrition and the standard of living of its people and the improvement of public health as among its primary duties ...."

प्रस्ताव में है कि वहां पर रोजगार के ज्यादा साधन उपलब्ध कराए जायें। वहां पर जो सार्वजनिक वितरण सप्लाई है उसमें गड़बड़ी है। निश्चित रूप से गड़बड़ी है। लोग अपना राशन कार्ड गिरवी रख देते हैं और गिरवी रखने के बाद उनको वापस नहीं लेते, इसलिए कि उनके पास क्रय शक्ति नहीं है।

तीसरे, वहां पर व्यापक स्तर पर ग्रामीण रोजगार योजनायें शुरू करिए क्योंकि जब आप रोजगार शुरू करिएगा तो लोग वहां काम करेंगे और काम करने के के बाद उनको रोटी मिलेगी, उसके जरिये उनकी क्रय शक्ति बढ़ेगी। इसलिए मैं फिर अपनी बात को समाप्त करते हुए अपनी मित्र मजूमदार जी से यही कहूंगा कि श्रीमती सरला माहेश्वरी जी के प्रस्ताव में राहत कार्यों के लिए, त्रिपुरा के लोगों, वहां के आदिवासियों की सहायता के लिए जो मांग रखी गयी है कम से कम उसका तो समर्थन करें। अगर उसका आप समर्थन नहीं करेंगे तो मैं इस नतीजे पर पहुंचूंगा...

SHRI SUDHIR RANJAN MAJUMDAR : That I have mentioned in my speech. The State Government has taken up some schemes for development of the

[Shri Sudhir Ranjan Majumdar]

tribal areas and the tribal people. The Central Government should provide more funds so that these can be strengthened.

SHRI SUNIL BASU RAY : What steps have you taken? ...(*Interruptions*).

THE LEADER OF OPPOSITION (SHRI SIKANDER BAKHT) : I have to say just one word, Sir. Let us not make it a practice of just ignoring things by saying that you must have read it in the newspaper. That is the only way in which the people of this country are informed.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGESH DESAI) : I agree.

SHRI SIKANDER BAKHT : We should not make it a practice.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGESH DESAI) : That is all right.

SHRI SIKANDER BAKHT : This has been said in the morning, and this has been said now. This is a very wrong practice.

श्री सत्य प्रकाश मालवीय : तो अंत में केवल दो बातें निवेदित करना चाहूंगा जो कुछ मैंने जानकारी की है इस सिलसिले में उसके अनुसार वहां कोई एक झूम की खेती होती है, वह असफल हो गयी है इसलिए लोगों को खाने को नहीं मिलता, क्रय शक्ति नहीं है वहां के जंगलात में किसी किस्म का कोई बेर होता है उस को लोगों को पेट भरने के लिए खाना पड़ता है तथा उस बेर को खाकर लोग बीमार पड़ते हैं और इसके कारण भी वहां पर मौतें होती हैं। मंत्री जी जब अपना उत्तर देंगे तो निश्चित रूप से बतायेंगे कि क्या यह बात सही है कि नैसर्गिक जंगलात के जो घास हैं, बेर हैं वे उसको खाते हैं और खाने के बाद बीमार पड़ते हैं और मौतें होती हैं।

इसलिए मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करते हुए यह बात भी कहना चाहूंगा कि त्रिपुरा की हालत इतनी चिंताजनक, इतनी दयनीय है कि वहां पर सारी समस्याओं का अध्ययन और बाद में उसका निदान और सुझाव देने के लिए एक राज्य सभा और लोकसभा में संसद सदस्यों की टीम वहां पर जानी चाहिए जो एक-दो या तीन दिन वहां पर रहे और जाकर अध्ययन करके सरकार को रिपोर्ट करे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इसका समर्थन करता हूं।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGESH DESAI) : Just a minute. Shri M.M. Jacob, the Minister of State in the Ministry of Home Affairs, will make a statement regarding recovery of a huge quantity of arms and ammunition in Ahmedabad, Gujarat, at five o' clock today, immediately after the Private Member's Resolution.

श्री अनन्तराय देवशंकर दवे (गुजरात): क्लैरिफिकेशन आज ही होंगे।

उपसभाध्यक्ष (श्री जगेश देसाई) : वह बाद में देखेंगे।

Let him make the statement. At that time I will take the sense of the House.

SHRI SIKANDER BAKHT : It is important. It is already a scheduled business.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGESH DESAI) : Still there are two statements on which clarifications are to be made.

SHRI SIKANDER BAKHT : Then how can he make a statement and give clarifications in this House?

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGESH DESAI) : We will decide at that time whether we should have clarifications today or on Monday.

श्रीमती सत्या बहिन (उत्तर प्रदेश) : धन्यवाद उपसभाध्यक्ष महोदय। माननीया सदस्या श्रीमती सरला माहेश्वरी का मैं बहुत सम्मान करती हूं।

उपसभाध्यक्ष (श्री जगेश देसाई) : आप दो-तीन मिनट में खत्म कर दीजिए।

श्रीमती सत्या बहिन : बिल्कुल दो मिनट लूंगी। बिल्कुल संक्षेप में बोलूंगी।

उपसभाध्यक्ष (श्री जगेश देसाई) : बोलिए।

श्रीमती सत्या बहिन : महोदय, मैं माननीया सरला माहेश्वरी जी का बहुत सम्मान करती थी लेकिन आज यह जो संकल्प लाई हैं इससे मुझे ऐसा आभास होता है और मेरा जो विश्वास है उसको काफी ठेस पहुंची है, मुझे दुःख हुआ है **(व्यवधान)**

उपसभाध्यक्ष (श्री जगेश देसाई) : बोलिए-बोलिए। आप बोलिए। **(व्यवधान)** आप यहां देखिए, वहां मत देखिए।

श्रीमती सत्या बहिन : यह आपका विषय नहीं है। **(व्यवधान)** महोदय, यह संकल्प जो लाया गया है कि त्रिपुरा में लगभग चार सौ लोग भूख और भूख से पीड़ित बीमारियों से मरे हैं, यह सच्चाइयों से बिल्कुल परे है और मैं पूरी तरह कह सकती हूं कि यह संकल्प एक राजनीतिक संकल्प है। यह वहां की सरकार पर दोषारोपण करने के लिए राजनीतिक प्रहार करने के लिए यहां लाया गया है। हालांकि त्रिपुरा और वहां भौगोलिक परिस्थितियां ऐसी हैं कि वहां पर अकसर अतिवृष्टि, अनावृष्टि और इससे संबंधित समस्यायें पैदा होती रही हैं। लेकिन उसका राजनैतिक लाभ उठाना मैं समझती हूं कि उससे पीड़ित लोग और वहां के लोग जो संकट में हैं या जिनको परेशानी हो रही है उन लोगों का पूरी तरह से उपहास है। न केवल उन्हीं लोगों का बल्कि मानवता का यह उपहास है, जिसकी मैं पूरी तरह से निंदा करती हूं, जो इस संकल्प में लाया गया है, अगर उसको छोड़ दिया जाए और माननीय दृष्टिकोण से और दलों से ऊपर उठकर अगर हम विचार करें तो अकेले एक त्रिपुरा की समस्या नहीं बल्कि देश भर में कहीं पर भी हो, उसको अनदेखा नहीं किया जा सकता। महोदय, चाहे वह उड़ीसा के कोरापुट और कालाहांडी क्षेत्रों के आदिवासियों की दुर्दशा हो और चाहे वह बस्तर और सरगुजा और झाबुआ में जो आदिवासियों पर वहां पर बीत रही है उनकी हालत को अनदेखा नहीं किया जा सकता। लेकिन इसके लिए मैं एक निवेदन करना चाहूंगी कि जो भी सदस्य बोल रहे हैं या बोलेंगे उनको एक रही, ईमानदारी से एक विचार देना चाहिए, सुझाव देना चाहिए कि देश भर में अगर ऐसी तकलीफें आती हैं तो हमें क्या करना चाहिए। मुझे यह कहते हुए खुशी महसूस होती है कि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा गरीबों के प्रति, आदिवासीयों के प्रति, दलितों के प्रति उनके कल्याण के लिए जो प्रतिबद्धता जाहिर की है, न केवल अपने बयानों में, अपने घोषणा-पत्रों तक ही सीमित नहीं बल्कि काम करने में भी **(व्यवधान)**

एक माननीय सदस्य : भुखमरीका यही तो कारण है।

श्रीमती सत्या बहिन : आप पहले मध्य प्रदेश की बात तो करिए। मध्य प्रदेश को क्यों भूल जाते हैं। वहां पर भुखमरी नहीं है फिर भी लोगों को गोलियों से भून दिया जाता है **(व्यवधान)** राजस्थान में भुखमरी नहीं है वहां तो **(व्यवधान)** फिर भी वहां लोगों को गोलियों से भून दिया जाता है। आप लोगों को... **(व्यवधान)**

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGESH DESAI) : It is a matter of concern if it happens anywhere in the country. It is very important. Let us not fight on that.

श्रीमती सत्या बहिन : वहां पर लोगों को गोलियों से भून दिया जाता है और भूखे लोगों की तो बात ही दूसरी है। अपनी बात बोलिए। मान्यवर, सन 1977 से आसपास गैर-कांग्रेसी सरकारें नहीं हैं वहां। त्रिपुरा सीमावर्ती राज्य है।

[श्रीमती सत्या बहिन]

तकलीफें किसी भी इंसान की हों, किसी भी प्रदेश की हों, मगर पूरा देश एक है। अब पूरे देश में कहीं भी तकलीफ होती है, कहीं भी कोई परेशानी होती है, चाहे वह आपात विपदा हो, चाहे प्राकृतिक विपत्ति हो, चाहे मानवीय विपत्ति हो, पूरे देश में तकलीफ सबको होती है।

उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन यह करना चाहती हूं कि हमारी जो वितरण प्रणाली है, उसको दुरुस्त किया जाना चाहिए। हमारे देश में आज खाद्यान्न की इतनी कमी नहीं है, जितनी कि दिखाई जाती है। सही मायनों में, मैं समझती हूं हमारे जो खाद्यान्न हैं या जो खाद्य सामग्री है, उसकी बहुत बर्बादी होती है, उस पर अंकुश लगना चाहिए और केन्द्र सरकार को एक सुरक्षित अन्न भण्डार निश्चित करना चाहिए। यह सभी राज्यों के लिए होना चाहिए। जहां कहीं भी अगर कोई परेशानी हो, कोई तकलीफ हो तो वहां पर उसको पहुंचाया जाए।

उपाध्यक्ष महोदय, समाचार पत्रों में यह भी आया है कि बांगला देश में बड़े पैमाने पर तस्करी होती है, जो खाद्यान्न वहां पहुंचता है वह बंगाल के रास्ते से, त्रिपुरा के रास्ते से वहां बांगला देश में पहुंच जाता है। उस पर भी अंकुश लगाने की जरूरत है।

उपसभाध्यक्ष महोदय, सभी सदस्यों का हमारा एक नैतिक दायित्व हैं। हम चाहे किसी भी दल के हों, दल से ऊपर उठकर मानवीय दृष्टि से इस तरह की बातों को सत्य और निष्ठा से लेना चाहिए। हम अपने क्षेत्रों में अपने समाज में, अपने दलों से इस बात की धारणा लेकर आते हैं कि हम ईमानदारी से दलों से ऊपर उठकर जनता की सेवा करेंगे, लेकिन यहां आकर जनता को तो भूल जाते हैं, दल की सेवा करने लग जाते हैं।

उपसभाध्यक्ष महोदय मैं इस में ज्यादा नहीं बोलूंगी लेकिन इतना ही कहूंगी कि यह संकल्प राजनीतिक के दृष्टिकोण से लाया गया है इसलिए इसको वापस ले लिया जाए। इसकी मैं निन्दा करती हूं। इस संकल्प को वापस लेने के लिए मैं अनुरोध करूंगी ही। हमेशा चाहे त्रिपुरा की बात हो चाहे कोई बात हो, जहां महिलाओं का मामला आया है, हमने हमेशा एकजुट होकर इस सदन में उसे उठाया है।

एक माननीय सदस्य : उठाया तो सपोर्ट दें।

श्रीमती सत्या बहिन : हमने हमेशा एकजुट होकर इस सदन में उठाया है, चाहे कोई मामला हो बशर्ते वह ईमानदारी से लाया गया हो। मगर यह राजनीतिक दृष्टिकोण से लाया गया हैं इसमें कोई ईमानदारी है ही नहीं तो कैसे समर्थन कर सकती हूं।

उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगी, इतना ही कहूंगी और साथ ही यह भी कहूंगी कि त्रिपुरा की सरकार जो कुछ कर रही है वहां के भौगोलिक दृष्टिकोण से और वहां के रिसोर्सेज को देखते हुए वहां के लोगों के लिए जो कुछ कर रही है उसकी तो मैं प्रशंसा जरूर करूंगी। उसको अनदेखा नहीं किया जा सकता है। अगर अनदेखा करेंगे तो यह एक बेईमानी होगी। तो मैं उसकी प्रशंसा करते हुए माननीया सरला माहेश्वरी जी से निवेदन करती हूं कि वह संकल्प को वापस ले लें। धन्यवाद।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGESH DESAI) : I must say that the mover of the Resolution has very cleverly drafted it. She has said that a number of deaths took place in the Tribal areas of Tripura "due to starvation and hunger-related diseases, with the newspaper reports quoting the number of deaths as exceeding 400". The Resolution has been very cleverly worded.

PROF. SAURIN BHATTACHARYA : Mr. Vice-Chairman, Sir, I should say the Resolution really has not been cleverly drafted but drafted in the spirit in which a Resolution should be drafted. This Resolution highlights the serious problems affecting the Tribals in Tripura. The starvation deaths that they are reported to have been faced with is not this year's or that year's problem. Really for the Tribals all over the country such serious problems are not anyhow totally absent. But this Resolution particularly concerns itself with the conditions of the Tribals in the State of Tripura. Unfortunately, I could not listen to the full speech of aformer Chief Minister of Tripura, now an hon. colleague of ours, who had to quit under the pressure of circumstances which is well known in political circles at least. But, whatever I could listen to was not at all enlightening as would have been expected from a Chief Minister who should have known the State over which he ruled, ins and outs. I mean, at least his speech does not impress me like that. "Politically motivated" is a very peculair term. Here, we are all political people divided along political lines, the seats being allotted political party-wise. And, whenever an issue comes, it is said, 'with political motive this is being done'. What for are we here? There must be politics. But, besides politics, there is the question of justice also. That is what is more important. If justice is on my a side, then what I state will carry weight at least we would expect it to and who denies that consideration should be said to be motivated in a partisan manner. What is said here is that 400 tribal people have died either from starvation or starvation-promoted diseases. I was having a talk with my party Member in the Lower House, Mr. Samant Mandal. He went along with a team to see for themselves the condition obtaining in that part, particularly the North District of Tripura. What they have seen is that during the summer, when rivers have no water, tribal people dig out water and drink that and that water is really contaminated. They have to eat a plaintain type fruit which develops stomach ailments leading to their death. This is common in those areas. That problem has been highlighted. It is not a question whether it is Samir Ranjan Burman's Government or whether it was Nrupen Chakravarty's Government. The Left Front Government, of which our party was also a partner, ruled over Tripura for quite a long time. The Left Front clearly stated that in the present economic and social system and under the present Constitution, no radical reform in the condition of the people is possible. That was the position and they tried to do as best as they could. But they are no more there. Those who are there will have to bear the responsibility of governing the State. or quit. There is no other way. But, here, the hon. Member, Shrimati Sarala Maheshwari, did not travel that drastic path. She has only said that the quantum of the things given to these people through the PDS should be doubled so that the greater intake may help their longevity.

The other suggestion is: rural employment scheme be launched on a large scale so that they can develop some purchasing power; so that they do not suffer; so that their awakening may compel the Government to supply drinking water in those remote areas incurring even big expenses.

Thirdly, adequate medical relief measures should be undertaken for the treatment of people suffering from hunger-related diseases. I do not know to which of these suggestions exception could be taken from the Congress Benches, from the side of the Government. The Chair has called it a cleverly drafted resolution. I will say it has been very soberly drafted in which the problem has been highlighted and there has been no attempt to castigate the ruling party at the moment. But, then, those who have a guilty conscience, are pricked by everything. What the Congress Government has done for the poor people, for the

[Prof. Saurin Bhattacharya]

tribal people and for the Scheduled Caste people, can very well be known from the percentage of the people below the poverty line. And who are they? So only sweet words won't carry us very far if we do not take concrete steps to ameliorate their conditions but just blame anybody, who raises the issue, with political motives. That won't carry them very far. Therefore, let them try to respond to the situation. This resolution offers them an opportunity for that. Let them try to avail themselves of that opportunity without trying to make, like Tweedledum and Tweedledee, a distinction between this and that, without facing the burning problems of the tribal people of Tripura fairly and squarely.

श्री मूलचन्द मीणा (राजस्थान) : उपसभाध्यक्ष महोदय श्रीमती सरला माहेश्वरी द्वारा जो संकल्प पेश किया गया है वह अखबारों की रिपोर्टस के आधार पर है । इससे लगता है कि इनकी मंशा आदिवासियों के हित की नहीं है । इनका एक उद्देश्य है कि आदिवासियों के के नाम पर प्रचार किया जाए और द वासियों को भुलावा देकर कैसे अपना राजनीतिक स्वार्थ सिद्ध किया जाए । इनकी मंशा इससे साबित होती है । मैं यह कहना चाहता हूं कि आजादी के बाद इस देश की सत्ता कांग्रेस सरकार के हाथ में आई । आदिवासी अनुसूचित जाति के लोगों के लिए कांग्रेस की सरकार ने ऐसी योजनाएं बनाई जिनके माध्यम से चाहे वह राजस्थान का आदिवासी हो, चाहे बिहार का आदिवासी हो, चाहे त्रिपुरा का आदिवासी हो और चाहे महाराष्ट्र का आदिवासी हो, उनका विकास हुआ है । आदिवासी क्षेत्रों में रहने वाले आदिवासी लोग अनपढ़ भी थे, कम समझदार भी थे, शोषण भी उनका होता था । उनका शोषण लोग आज भी करते है । इसलिए इनका विकास तेजी से नहीं हो पाया है ।

उपसभाध्यक्ष (श्री जगेश देसाई) मैं भी आदिवासी इलाके से आता हूं ।

श्री मूलचन्द मीणा मैं भी आदिवासी हूं इन आदिवासियों का शोषण भी किया जाता था । शोषण करने वाले लोग अब भी उनका पीछा नहीं छोड़ते है । जो भी योजना सरकार के माध्यम से इनके विकास के लिए लागू की गई है, उन योजनाओं को लागू करने के अंदर भी दोष है । जितना पैसा आदिवासियों के विकास के ऊपर खर्च करना चाहिए उतना पैसा खर्च नहीं होता है । उस पैसे को, बीच के जो दलाल हैं और शोषणकर्ता हैं वे अपनी जेबों में रख लेते हैं । मैं कृषि मंत्री जी का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि राजस्थान के आदिवासी एरिया के अंदर आदिवासियों को कृषि के नए तरीकों के बारे में शिक्षित करना चाहिए । आदिवासी मेहनती होता है जितनी मेहनत आज राजस्थान का आदिवासी करता है दूसरा कोई राजस्थान में नहीं कर सकता है । लेकिन उनका शोषण होता है । मैं यह कहना चाहता हूं कि कांग्रेस की सरकार ने आदिवासियों के विकास के लिए बहुत कुछ किया है । सरला जी का जो उद्देश्य था इस प्रस्ताव को लाने का, केवल बातें करने का है और कांग्रेस का उद्देश्य आदिवासियों का विकास करना और प्रैक्टिकल काम करना है लेकिन जो आदिवासियों की बात करते हैं उनका केवल एक उद्देश्य है आदिवासियों को बहलाकर वोट प्राप्त करना ।

सरला जी ने आदिवासियों के हितों के लिए कुछ सुझाव रखे हैं । उनमें एक एक सुझाव यह है कि जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली है उसमें दोष है, अतः उसे बदला जाए । मैं भी मानता हूं कि राजस्थान के अंदर अकाल पड़ने के बाद भी राजस्थान की सरकार आदिवासियों के साथ कैसा व्यवहार कर रही है ? राजस्थान के आदिवासी एरिया के अन्दर अकाल पड़ने के बाद भी अकाल राहत कार्य नहीं खोले गए, लोगों को दवाइयां उपलब्ध नहीं हो रही हैं । यहां तक कि राजस्थान के अन्दर जो आदिवासी एरियाज हैं बांसवाड़ा, उदयपुर, कोटा,

इन एरियाज में तो डाक्टर जाते ही नहीं। इसलिए मैं यह चाहता हूं कि आदिवासियों के विकास के लिए, आदिवासियों के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए, एक योजना बने जिससे इन लोगों को दवाइयां और काम मिल सके। इसके लिए आप एक नयी संस्था स्थापित करें जिससे आदिवासियों का विकास समय रहते हो सके।

महोदय, मैं इस संकल्प का विरोध करता हूं। इनके दिल के अंदर आदिवासियों के हित की भावना नहीं है। केवल उन्हें बहलाकर वोट प्राप्त करने की भावना है। इसलिए जो प्रस्ताव ये लाई हैं और अखबारों के माध्यम से लाई हैं, मैं उसका विरोध करता हूं।

श्री संघ प्रिय गौतम : मांगों का तो समर्थन कर दो, प्रस्ताव का भलेही विरोध करो। आदिवासियों का भला कैसे होगा।

श्री अनन्त राम जायसवाल (उत्तर प्रदेश) : माननीय सभापति जी, श्रीमती सरला जी का यह संकल्प मेरी राय में उनकी संवेदनशीलता का परिचायक है और इंसानी मौतों या कष्ट के समय एक इंसान की जो पीड़ा, तकलीफ और हमदर्दी होती है, उसी भावना के साथ वह यह संकल्प लाई हैं। प्रस्ताव बिल्कुल सीधा-सादा है। उसमें भूख या भूखजनित बीमारियों से मरने वाले 400 आदिवासियों की मौत पर चिंता व्यक्त की गई है और भारत सरकार से मांग की गई है कि वह त्रिपुरा को ज्यादा राशन आवंटित करे, वहां पर ज्यादा रोजगार के अवसर पैदा करे और दवाई और और इलाज का प्रबंध करे। यह इसमें मांग की गई है। तो यह प्रस्ताव इतना मासूम है कि इस पर किसी प्रकार की टिप्पणी की गुंजाइश नहीं है। किन परिस्थितियों में उनको यह प्रस्ताव लाना पड़ा, उस पर जरा ध्यान दीजिएगा। पहली चीज तो यह है कि जिनके बारे में प्रस्ताव लाया गया है, वह और अगर पूरे त्रिपुरा को देखे तो भी वहां की बहुसंख्य आबादी गरीबी की रेखा के नीचे हैं। दूसरी चीज यह है कि अतिवृष्टि के कारण वहां पर फसल बरबाद हो गई है। तीसरी चीज यह है कि वहां पर लोगों के पास काम नहीं है। तो इन तनों चीजों ने ऐसी हालत पैदा कर दी कि लोगों की क्रय शक्ति पूरी तरह से समाप्त हो गई और ऐसी हालत में वहां लोग मर रहे हैं। इस पर भी सरकार की संवेदनशीलता देखिए। ऐसी पत्थरदिली तो मुश्किल से दिखाई देगी। दूसरी सी. पी. एम. के जो मुख्य मंत्री थे, नृपेन चक्रवर्ती जी, उन्होंने इस हालत के बारे में प्रधान मंत्री जी को भी एक ज्ञापन दिया था। वहां की सरकार की तरफ से कोई कार्यवाही न होने के कारण सरला जी ने यहां यह संकल्प रखा। सरकार की पत्थरदिली का परिचय इससे मिल जाता है कि लोग मर रहे हैं और सरकार के मंत्री कहते हैं, स्वयं मजूमदार जी जब वह मुख्य मंत्री थे, तो उन्होंने स्वीकारा है कि 400 नहीं 200 लोग मरे हैं ....

SHRI SUDHIR RANJAN MAJUMDAR : Not more than ten.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGESH DESAI) : He said about both starvation and diseases.

श्री अनन्त राम जायसवाल : आपने 10 तो माना कि 10 लोग मरे हैं। तो मान लीजिए,

महोदय, इनका कहना यह है कि ये भूख से मौतें नहीं हुई और दूसरी तरफ ये खुद कहते हैं कि अन्न का भारी संकट है त्रिपुरा में। सरकारी गोदामों में अन्न की कमी है। यह खुद इन्होंने माना है और सौभाग्य है कि सदन में यह मौजूद हैं। यह बात सही है कि नहीं यह ये बता सकते हैं। इन्होंने खुद माना है कि त्रिपुरा में फसल के खराब होने के कारण और सरकारी गोदामों में अन्न की कमी होने के कारण अन्न का भारी संकट है और यह भी माना है कि वहां पर ऐसे मौसम में लोगों को काम नहीं मिलता है। तो जब यह हालत होगी तो वहां पर लोगों के पास क्रय शक्ति नहीं है तो उस क्रय शक्ति को प्राप्त करने के लिए जो लोगों को राशन कार्ड मिले हैं वह भी वे गिरवी रखने पर मजबूर हुए। यहां तक कहा गया है कि अपने बच्चों को वह बेच रहे हैं। यह भी कहा गया है कि दूसरे राज्यों को वह पलायन कर रहे हैं। इसमें सरकार ने भी माना है कि उनके पास काम नहीं है। काम नहीं है, अनाज की कमी है, लोगों की क्रय शक्ति नहीं है तो लोगों को खाना नहीं मिलेगा तो वह कुछ तो खाएंगे। जब खाना

[श्री अनन्तराम जायसवाल]

नहीं मिलेगा तो मरने वाले भूख से नहीं मरेंगे तो किससे मरेंगे? जब उनको अन्न नहीं मिलेगा तो पेट की आग ऐसी होती है कि उसको बुझाने के लिए जहरीली जड़ों को खा रहे हैं, पेड़ों की छालों को खा रहे हैं। तो किसी को कालरा होगा, किसी को गैस्ट्रो इंटराइटिस होगा। यहां पर मैं दूसरी बात यह कहना चाहता हूं कि भूखमरी के लोग शिकार होते हैं तो सरकार की तरफ से कहा जाता है कि गैस्ट्रो इंटराइटिस से मरे हैं कालरा से मरे हैं या दूसरी इसी तरह की बीमारियों से ऐसी मौतें हुई हैं। तो यह मामला कब तक चलेगा? मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि यहां पर जब आंध्र प्रदेश में भूख से मरने वाले बुनकरों की बात उठी थी तो हमारे कपड़ा मंत्री ने माना था कि ऐसे ही जब राजस्थान में लोगों को खाना नहीं मिला था तो उन्होंने माना था कि खाना न मिलने की वजह से लोग मरते हैं। लेकिन जो दूसरे हठी लोग हैं, मंत्री हैं जिनका दिल पत्थर का हो जाता है वह यह करते हैं कि ये मौतें भूख से नहीं हुई। क्यों नहीं आप स्वीकार करते? अगर आप इस चीज को स्वीकार करेंगे तो शायद इसका कोई इलाज निकल जायेगा। मैं यह कहना चाहूंगा कि डाक्टरों की एक्सपर्ट कमेटी बैठा दी जाए। मैं यह मांग करता हूं कि जब मंत्री जी बोलें तो उस वक्त कोई आश्वासन दें कि डाक्टरों की एक्सपर्ट कमेटी बैठा दी जायेगी। उसका टर्म्स आफ रिफरेंस यह रहेगा कि अगर आदमी को ज्यादा दिन तक खाना नहीं मिलेगा अन्न नहीं मिलेगा तो क्या वह मरेंगे। क्या वह भूख से हुई मौत होगी। इस तरह से लोग मर रहे हैं लेकिन सरकार इस बात को हमेशा दोहराती रहती है कि भूख से मौतें नहीं होती। यह पत्थर दिली की वजह से है। इसी पत्थर दिली की वजह से सरकार की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं होती। जब सरकार की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं होती तब ही श्रीमती सरला माहेश्वरी को ऐसा संकल्प सदन में लाना पड़ता है। दूसरी राय मेरी यह है कि इस संकल्प को बगैर बहस के पास कर देना चाहिए। ऐसे मसले पर भी हम लोग इतनी लम्बी चर्चा कर रहे हैं। यह बहस तो कभी खत्म नहीं होगी। लोग भूख से मरते रहेंगे, बीमारी से मरते रहेंगे। आखिर यह बीमारी कैसे पैदा हुई? अगर बीमारी की जड़ मालूम हो जायेगी तो उसकी तरफ क्या सरकार का ध्यान नहीं जायेगा? यह जो त्रिपुरा में हो रही है यह एक साल की बात नहीं है बल्कि पिछले कई सालों से यह बात हो रही है। जब यह हालत वहां पर बराबर रही है तो इसका इलाज क्यों नहीं निकाला गया अभी तक। चाहे जिस भी पार्टी की सरकार वहां रही हो, यह कोई तर्क नहीं है कि सी०पी०एम० के वक्त कोई काम नहीं हुआ और उस समय हालत ज्यादा खराब हुई इसलिए हम भी कुछ नहीं करेंगे। यह जो अकर्मण्यता की बात है यह क्षम्य नहीं है। आज जो सरकार है यह चुप है। उन्होंने इसका हल क्यों नहीं निकाला? मेरा यह नम्र निवेदन है कि योजनाबद्ध विकास पर यह बहुत ही शंकापूर्ण और शर्मनाक टिप्पणी है। अभी तक देश में न तो साफ पानी मिल रहा है और न भरपेट अन्न मिल रहा है। इस तरफ सरकार का ध्यान जाना चाहिए, यह मेरा निवेदन है।

दूसरी चीज यह कहना चाहता हूं कि लोगों के पास राशनकार्ड ही नहीं है। खुद श्री मजूमदार ने भारत सरकार से मांगा था, जब यह वहां पर मुख्य मंत्री थे, कि भारत सरकार इनको ज्यादा अन्न आवंटित करे। क्यों यह मांग की गई थी? पैसा भी इन्होंने ज्यादा मांगा था कि और ज्यादा पैसा दिया जाए। अगर यह हालत वहां नहीं थी तो इन्होंने ऐसी मांग क्यों की थी? इनकी मांग पर भारत सरकार ने, जो अखबार में खबर आई है 12 हजार टन से बढ़ाकर 16 हजार टन अनाज वहां भेजा है कुछ पैसा भी भेजा होगा। हालत यह है कि आप खुद मान रहे है दूसरे शब्दों में कि यह चीज है। लेकिन सबसे बड़ी चीज जो मैं मानता हूं वह यह है कि लोगों के पास क्रय शक्ति नहीं है तो फिर चाहे राशन डबल कर दें कुछ होने वाला नहीं है। वहां पर भ्रष्टाचार व्याप्त है। भ्रष्टाचार के रहते अन्न की तस्करी होती रहेगी। उसके रोकने का कोई उपाय नहीं निकल रहा है। बंगलादेश और भारत के बीच जो सीमा है उसमें न समुद्र है, न पहाड़ है, खाली कांटेदार तारों की बाड़ लगा दी गई है। वहां पर बी०एस०एफ० के लोग मौजूद हैं। उनके मौजूद रहते

हुए बंगलादेश से लोग आते हैं और हमारे देश के लोग वहां जाते हैं । वह अपना सामान यहां लाते हैं और बेचते हैं, उसके बदले दूसरी चीज ले जाते हैं । यह रोज चलता है । इसके साथ तस्करी भी अन्न की वहां पर होती है । यह बराबर शिकायत मिल रही है । इसको रोकने का उपाय किया जाए ? यह सबसे जरूरी चीज है कि लोगों के लिए कमाने के ज्यादा अवसर पैदा किये जायें । जब तक गेनफुल एम्पलायमेंट नहीं मिलता है उनको, तब तक इस समस्या का कोई भी इलाज नहीं निकाला जा सकता । बरसात में यह तकलीफ और ज्यादा बढ़ जाती है, संकट और गहरा जाता है । क्योंकि वहां पर आने-जाने के रास्ते बंद हो जाते हैं । अखबारों में छपा है, मालूम नहीं सही है या गलत । आप इस तरफ भी ध्यान दीजिएगा कि वहां पर कांग्रेस के विकल्प में सी.पी.एम. अकेली पार्टी है । और किसी दूसरी पार्टी का, जहां तक मैं जानता हूं, वहां कोई वजूद नहीं है । जब वहां पर यह हालत है तो जाहिर है कि सबसे पहले आवाज सी.पी.एम. पार्टी उठाएगी और उनका जो अखबार 'देशार कथा' है उसने इन चीजों को छापना शुरू किया । हालत यहां तक बिगड़ी कि कांग्रेस के जो कोलिशन पार्टनर हैं त्रिपुरा उपजाती युवा समिति के एक्टिविस्ट ... (**व्यवधान**) ।

श्री सुधीर रंजन मजूमदार : वहां पर सी.पी.एम. है ही नहीं ।

श्री अनन्त राम जायसवाल : आप इस ख्याली दुनियां में मत रहिये । अभी वहां नहीं है इन हालात के चलते पैदा हो जाएंगे । उन लोगों ने भी आवाज उठाई और हालत बिगड़ती गई । इसलिए मैं माननीय मंत्री जी (श्री मजूमदार) से यह जानना चाहता हूं कि क्या यह सही नहीं है कि भूख को मिटाने के लिए कुछ लोगों ने सरकारी गोदामों को लूटने की कोशिश की उसमें कौन लोग सरीक थे ? क्या यह सही नहीं है कि आपके जो कोलिशन पार्टनर हैं उनके एक्टिविस्ट्स की अगवाई में लोग वहां गये और उन पर गोली चलाई गई ? ोग मारे गये । यह आज की बात नहीं है । 1988 में यह हुआ है और 1989 में यह हुआ है और आज हम 1992 में हैं । यह एक दिन की घटना नहीं है, रोज वहां ऐसी घटनायें हो रही हैं । उन्होंने इसकी आवाज उठाई है । यह इतना गहरा संकट था कि इसका असर आपके कोलिशन पार्टनर पर पड़ा और आपको गवर्नमेंट छोड़नी पड़ी जिसके नतीजे के तौर पर आप यहां बैठे हैं और श्री समीर रंजन वहां मुख्य मंत्री हो गये हैं । यह सब उस संकट की देन है । आप यहां आ गये हैं और वे वहां मुख्य मंत्री बन गये हैं । फिर आप बराबर कहे जा रहे हैं कि वहां कुछ नहीं हुआ है, कोई नहीं मरा है । मेरा निवेदन है कि इसको पार्टी का सवाल न बनाया जाय । इसलिए मैं आपके माध्यम से, उपसभापति जी, सदन से यह अपील करूंगा कि इस रिजोल्यूशन को सर्वसम्मति से पास किया जाय और जो दुखी आदिवासी लोग हैं, जिनके बारे में अभी मालवीय जी ने संविधान का हवाला दिया है, उनके नरिशमेंट की जिम्मेदारी सरकार की है, उनको भर पेट खाना देने की जिम्मेदारी सरकार की है । हमें उन्हें अन्न और पानी देना है । इसलिए मंत्रीजी आप उनके लिए काम के अवसर पैदा करने करने का तुरन्त प्रबन्ध कीजिये । अंत में मैं सरला जी को धन्यवाद देता हूं कि वे इस संकल्प को लाई और उसके द्वारा इस सदन के सदस्यों और सदन का ध्यान इस ओर खींचा ।

श्री शिव प्रताप मिश्र (उत्तर प्रदेश) : माननीय उपसभाध्यक्ष जी, मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं जो आपने मुझे श्रीमती सरला माहेश्वरी जी के संकल्प पर अपनी बात कहने का अवसर दिया । उन्होंने इसमें दो मुद्दे उठाये हैं । इस संकल्प में आदिवासियों के लिए उनकी जो भावना है उसका तो हम आदर करते हैं, लेकिन उनका जो राजनैतिक उद्देश्य है वह सोचनीय है और समीक्षा के योग्य है । हमारे देश में आदिवासियों को 15 अगस्त, 1947 में स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद जो सम्मान कांग्रेस ने दिया है वह हमारे यहां ही नहीं, संसार में एक उदाहरण की तरह इतिहास में रहेगा ।

श्री संघ प्रिय गौतम : आज तक एक भी आदिवासी केबिनेट मिनिस्टर नहीं बना है, इतना सम्मान दिया है आपने ।

श्री शिव प्रताप मिश्र : मैं आपको बता रहा हूं । चन्द्रगुप्त मोर्य आदिवासी था । उसका पुत्र बिन्दुसार था और उसका पुत्र सम्राट अशोक था और सम्राट अशोक का स्तम्भ तीन मूर्ति यहां पर लगा हुआ है और आपके सामने है और यह राज्य सभा में, लोक सभा में, राष्ट्रपति भवन में, प्रधान मंत्री के यहां और आपके पत्र-पटल पर छपा हुआ है । यह आदिवासी थे क्योंकि इसका ऐतिहासिक प्रमाण है । उसकी मानसायरी जन्मपत्री में जो वर्णन किया गया है उसकी कुण्डली में सशक्त शशक योग था ।

वनेशु दुर्गेशु न देषु सक्त: प्रियतिथिर्तानि मतिनर्भ्रन्य: जाना सेना निचय निरतो दन्तु-रश्चापि किंचि, धातोर्वदि प्रव्रजत यातो अत्र न संशय: ।।

वह चन्द्रगुप्त आदिवासी था उसका वर्णन किया गया है कि उसके खानदान के लोग वनों में रहते थे और दुर्ग के किनारे रहते थे और अपनी स्थानीय सेनाओं का संगठन करते थे । और दूसरों के कोष से परिचित थे । उसका पुत्र बिन्दुसार था । चन्द्रगुप्त मौर्य को चाणक्य ने सम्राट बनाया । वह आदिवासी था जिसने भारत का एकीकरण किया था । इसको भी मैं मानता हूं कि भारत पहले अंग-बंग और कलिंग तमाम खण्डों में बंटा हुआ था । लेकिन भारत को एक बनाने के लिये एक आदिवासी को चुनकर उसको सम्राट बनाया गया और उसको सम्राट बनाने के बाद उसका पुत्र बिन्दुसार हुआ और पौत्र अशोक । अशोक के स्तम्भ की तीन मूर्ति को आपके सामने 15 अगस्त, 1947 को ब्रतानिया सरकार की गुलामी की जंजीरों को तोड़कर यहां पर स्थापित कर दिया गया है । यह मैं आपके सामने एक उदाहरण के रूप में, आदिवासियों के सम्मान का जब यहां पर बात आई, तो मैंने कहा । आप यह कहें कि आदिवासियों को कोई सीट नहीं दी गयी तो जिसको आप आदिवासियों की रानी कहते हैं, विभू देवी वह त्रिपुरा की है और त्रिपुरा का ही यह विषय है । वे आपके संसद में हैं, लोकसभा में हैं । आदिवासियों के लिय आरक्षण का को प्रश्न है, आदिवासी कोई जाति नहीं थी, आदिवासी एक वर्ग था । यह जाति-पाति का जो ढांचा आज आपके सामने है यह ब्रिटिश साम्राज्यवाद की विभाजन करने, डिवाइड एंड रूल की पालिसी के तहत है, इस नीति के तहत हम लोगों को बांटा गया है । नहीं तो जो हमारी नीति थी उसमें था कि :

चातुर्वर्ण्यम-मया सृष्ट्वा गुणकर्म विभागश: या गीता ।

गौतम जी, हमारे यहां जो चार वर्ण बनाये गये थे, वे जन्म से नहीं थे बल्कि वे कर्म से थे । बाल्मीकी आदिवासी थे । लेकिन "उल्टा नाम जपत जग जाना बाल्मीकी भये ब्रह्म समाना" । बाल्मीकी को महर्षि बाल्मीकी कहा गया ।

उपसभाध्यक्ष (श्री जगेश देसाई) : मिश्र जी, अब रेजोल्यूशन पर आ जाइये । **(व्यवधान)** . . .

श्री विठ्ठलराव जाधव (महाराष्ट्र) : जो इन्होंने कहा है उसको मैं मराठी में बोलता हूं ।

उपसभाध्यक्ष (श्री जगेश देसाई) : Please, now you speak about Tripura बतलाइये वहां पर भुखमरी का क्या हाल है, क्या बात है ।

श्री शिव प्रताप मिश्र : उपसभाध्यक्ष महोदय, मेरे अंत:करण में पीड़ा हुई जब यहां पर यह बताया गया कि आदिवासियों का हम सम्मान नहीं करते । उसका उदाहरण मैंने आपके सामने प्रस्तुत कर दिया । आदिवासी कोई छोटी जाति नहीं है, यहां के मूल निवासी हैं । यह संयोग की बात है कि एक आदिवासी सम्राट, जिसका मैंने वर्णन किया उसके पौत्र के स्तम्भ को हमारी सत्ता ने चुना है ।

उसको हमारी सभा ने मान लिया है, उसको भी मान रहे हैं और मैं भी मान रहा हूं। इसमें कोई राजनैतिक उद्देश्य हो नहीं सकता। दूसरा मैं इसलिये आदिवासियों का कृतज्ञ हूं कि जिस काल को भारत का स्वर्णिम काल कहा जाता है, वह गुप्त साम्राज्य-काल था। गुप्त का अर्थ होता है जिसका स्पष्टीकरण न हो। उसको भी आदिवासी या मूल निवासी हम मानते हैं। जो समस्या आज हमारे सामने कश्मीर की है, इसी तरह की समस्या का समाधान चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य ने किस तरह से किया था, जब भारत पर शकों का आक्रमण हुआ था। अभी यहां पर पाकिस्तान की षडयंत्रकारी योजनाओं के तहत हमारे यहां आतंकवाद फैला हुआ है। इस बारे में वार्ता होने के बाद भी उसका कोई समाधान नहीं निकल सका है। तो क्या इसको हम युद्ध का प्रथम चरण नहीं मानते? यह हुआ था शकों द्वारा भारत में। वह भी आदिवासी था जिसका वर्णन हम अपने ऐतिहासिक उल्लेख में पाते हैं।

दत्वारुद्ध गति खसाधिपतये देवी ध्रुवस्वामिनी, यस्समाद् खण्डित साहसो निववृतो श्रीशर्मगुप्तोनृपः तस्मिन एव हिमालये गिरि गुहाम कोणिन्न क्वणिन् किन्नरिन। गीयन्ते तव कार्तिकेय नगरे स्त्रीणाम गणम कीर्तियः

वह भी एक आदिवासी था। जब वे लोग आये तो उनको हटाने के लिये, उनका संहार करने के लिये उसने कश्मीर पर आक्रमण किया और उनको निर्मूल कर दिया। हमारी सीमायें सुरक्षित हो गई। उस हिमालय की कन्द्रा में वहां की दिव्यांगनाओं ने उनके यश और कीर्ति का गान किया। यह एक ऐतिहासिक तथ्य है **(व्यवधान)** दूसरी समस्या है अन्न की। आदिवासियों के सम्मान को मैंने पुष्ट कर दिया। अब अन्न की बात आई है। अन्न की कमी से त्रिपुरा में आदिवासी भूख से मर गये हैं। **(व्यवधान)**

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGESH DESAI) : May I request Mr. Satya Prakash Malaviya to *take the Chair.* ?

[The Vice-Chairman (Shri Satya Prakash Malaviya) In the chair]

श्री शिव प्रताप मिश्र : उपाध्यक्ष महोदय, आदिवासियों का सम्मान तो हुआ ही, आज पूरा भारत उनका सम्मान करता है। आदिवासियों के देवता भी भगवान जगन्नाथ हैं उड़ीसा में। लेकिन मैं आपको और भी बताना चाहता हूं कि उस अन्न के क्षेत्र में तो लाखों व्यक्ति प्रतिदिन खाते हैं लेकिन त्रिपुरा में जो कमी हुई चार सौ लोग भूख से मर गये, मैं सरला जी, की भावना से अलग नहीं हूं क्योंकि मैं उस सिद्धांत का हूं जिसमें अहिंसा और पर-पीड़ा का सिद्धांत है। जब मैं इस दरवाजे से बाहर निकलता हूं तो वहां गांधी जी की यह पंक्तियां लिखी रहती हैं कि वैष्णव जन तो तेने कहिये, ज पीड़ पराई जाण रे। यह कांग्रेस गांधी जी की पार्टी है, जिन्होंने भारत को स्वतंत्रता दी है। मैं उनके सिद्धांत से प्रेरित हो कर रन्ति देव के सिद्धांत को याद करता हूं जिसमें उन्होंने कहा कि—

नाहम कामये राज्यम् न स्वर्ग पुनर्भवाम। कामये दुःख तप्ताना प्रर्णिमनामार्ति नाशनम्॥

मैं संसार में न आपको चाहता हूं, न राज्य चाहता हूं, न स्वर्ग चाहता हूं, मैं जितने पीड़ित लोग हैं, उनकी पीड़ा का निवारण चाहता हूं।

श्री संघ प्रिय गौतम : यही तो सरला जी चाह रही हैं।

श्री शिव प्रताप मिश्र : गौतम जी, मैं उनकी इस भावना का आदर करता हूं। लेकिन बिना कारण के कार्य नहीं होता। न्यायशास्त्र में है अगर आपकी जबान है तभी आपके शब्द निकल रहे हैं। यदि कहीं धुआं है तो वहां आग है। जिस पर बौद्ध धर्म आधारित है—

जब अज्ञान है, अज्ञान से ही संवेदना है इसमें बिना ज्ञावे त्रिड भिज्ञाज। 'वत्स'

तो उस संवेदना म आपको मरने के बाद पुनः जन्म लेना होगा। जन्म लेने के बाद

[श्री शिव प्रताप मिश्र]

दुख है और सुख का कारण वह इच्छा है उसका निवारण का एक मार्ग है । तो उसके हिसाब से जो यहां पर दुर्घटना हुई है, उसकी जड़ में जाना है । इसको आपने नहीं समझा । जब से कांग्रेस सत्ता में आई है, उसने गरीबी हटाओ का नारा दिया और वाम-पंथी पार्टी सरकार जहां भी गई उसने कहा कि गरीबी भुखमरी बढ़ाओ **(व्यवधान)** मैं आपको बोल रहा हूं । इनका सिद्धांत मैं जानता हूं । मेरे मित्र भी हैं, सरला जी को मैं नहीं कह रहा हूं । यह वामपंथी सरकार थी जिसने वहां की प्रारंभिक इकाई बनाई । जैसे वृक्ष लगाने के बाद वृक्ष तुरंत फल नहीं देता है, जैसे जन्म के बाद शिशु अपना क्रियाकलाप प्रारंभ नहीं करता वैसे उनकी इकाई का यह दुष्परिणाम है । केंद्र से जो धन उनको जिस मद के लिए दिया गया वह धन दूसरी मद में व्यय कर दिया । **(व्यवधान)** खा गए । उससे धीरे धीरे पनपते हुए दुष्परिणाम के रूप में फल मिल रहा है । मैं कहना चाहता हूं **(व्यवधान)** मैं बताना चाहता हूं जो इन्होंने कहा है कि वहां उपभोक्ता वितरण प्रणाली ठीक की जाए, मैं चाहता हूं कि वहां जो कुछ रोजगार की बातें हैं यहां से केंद्रीय सरकार अपनी सर्वेक्षण टीम भेज कर देखे कि उसका पुनः दुरुपयोग तो नहीं हो रहा है । जो हमारे यहां रोजगार है इस समय वृद्धि है 1.6 प्रतिशत । और मांग है 3.4 प्रतिशत, उस हिसाब से उस अनुपात में वहां के कुछ लोगों को रोजगार भी दिए जाएं और औषधि भी । तो जिस राज्य में वस्त्र, औषधि, आवास, इन चीजों की व्यवस्था रहेगी उसमें भुखमरी नहीं होगी । मैं चाहता हूं कि अपने सिद्धांतों के अनुसार केंद्र सरकार उसका सर्वेक्षण करके समाधान करे । धन्यवाद ।

SHRI VIZOL (Nagaland) : Thank you very much, Mr. Vice-Chairman, Sir. I will not take much time.

When I look at this Resolution, I thank the Mover of this Resolution. When we took up this Resolution for consideration, it was said that it was politically motivated, that this was a political Resolution.

Sir, we are all political animals. We are all here for politics. Any statement made here in this House is political and any resolution moved in this House is polititical. We are all here for political purposes. But, when I look at this Resolution, I find that this a welfare Resolution, for the welfare of the people in this State. So, I think that this is worthy of consideration.

Well, Sir, Tripura is one of the seven sister States and we are all known to each other very well. It is very unwise on the part of our friends from Tripura to oppose this Resolution. You are all aware that Tripura was a princely State when it acceded to India and became a ful-fledged separate State in the Indian Union. The tribal people were submerged by the people from the plains, both from inside and outside the State. Now, these people are in the hills. The former Chief Minister said that they were engaged in shifting cultivation. It is because in their own lands they have become landless and that is why they are in the hills now eking out a living. Very often we find in the Press some stray news about deaths in Tripura due to some unknown disease. What kind of disease it is, I do not know. But, if it is a disease, then it must be some disease only. These people, because of poor diet, have lost their power of resistance to attack of any disease. There may be famine-related deaths also. So, it is said that some people died due to some disease. But everybody knows about it and nobody can deny it and denying it will be a sin on the part of anybody. So, the Mover of this Resolution, as has been said, has very cleverly drafted it. Whether it has been cleverly drafted or not, it is all about the welfare work for the welfare of the people of this State and I think that it would be very unwise to reject this Resolution. Any resolution for the welfare of the

poor and the downtrodden in any part of the country we have to support whether it is brought forward by this side or that side of the House. It is because we all know that today the minorities, the Tribals and the Harijans are all living in a very bad condition. We also know that a lot of atrocities are committed on these Tribals and Harijans. Harijans, according to the Father of the Nation, Mahatma Gandhi, are the children of God. Now, those who are weak are called by us as Harijans, minorities, Tribals, and low-castes. Today, the disparity in this country is very wide-rich, middle-class, and poor. Poor means ill-clad, ill-fed and who have no comfort. Even in this central part of the country, in this very capital of this country, just a few kilometers away, you will find a lot of women witn pitchers on their heads waiting in a long queue for a drop of water at the tap. This is the condition here even in this part of the country. But in States like Tripura, Nagaland and Mizoram, the Tribal people who were the owners of land, were driven to the hills by more wealthy people from the plains, from the neighbouring foreign countries. They are leading a very pathetic life. And to deny them food and cloth will be a sin. Therefore, it will be unwise on our part to reject this Resolution.

Sir, I support the Resolution. Thank you.

कृषि मंत्री (श्री बलराम जाखड़) : माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, श्रीमती सरला जी का यह प्रस्ताव मैंने देखा और जहां तक मैंने सारे माननीय सदस्यों के विचार सुने सब के भावों में जो अभिव्यक्ति हुई है, और जो कुछ उदगार मैंने सुने हैं उनमें मुझे न तो इस पक्ष का, न उस पक्ष का कोई खास अंतर नजर नहीं आया । पीड़ा तो सब के लिए एक है, व्यथा सब के लिए बराबर है और उस पीड़ा को बांटने के लिए चेष्टा करना मेरे ख्याल में सारे सदन का एक कर्तव्य ही है और उस कर्तव्य का सब ने पालन किया है । विचारों में थोड़ा मतभेद हो सकता है, कोई किस प्रकार से कहता है, कोई किस प्रकार से कहता है, लकिन जो है, उसमें मेरे ख्याल में सब का दृष्टिकोण सम है, एक जैसा है । त्रिपुरा का विषय उठाया गया और अखबारों में पढ़ा, सारा देखा, सही बात थी । कुछ न कुछ था, उठा । 1991 और 92 में जो भारी फ्लड आए, बाढ आई, उससे खेती नष्ट हुई । आप जानते है कि त्रिपुरा में ज्यादा झुम खेती करते हैं और झुम खेती के नष्ट हो जाने से गड बड हो जाती है । कुछ वह नालियां बनाकर पानी भी अच्छे-अच्छे झरनों का लाते हैं, वह सारा मामला धरम-भरम हो गया । उससे कष्ट हुआ, बीमारी का प्रकोप हुआ, सारी गडबड हुई और उसके कारण बीमारी फैली । उसको मौत का कारण, कुछ भी कर लें आप, मौत तो मौत है, आती है । कभी से भी आती है, बीमारी से भी, जिसमें प्रदूषण होता है उससे भी हो सकती है और हुई और उसके लिए चिंता सब के दिल में जो हुई उसके साथ मेरी भी हमदर्दी उसी प्रकार से है और मैं चाहता हूं कि इस प्रकार की कोई भी पुनरावृत्ति न हो दोबारा वह न देखना पडे, इसका उपकर्म हमें करना है और किस प्रकार हम उसकी रोकथाम कर सकते हैं वह हम सब का धर्म है ।

मैंने देखा है कि जिस तरीके से कुछ हुआ तो यहां सेंटर से टीम भेजी गई । जैसे ही पता लगा, यहां से सारी की सारी टीम भेजी गई, जिसमें डाक्टर लोग थे, स्पेशलिस्ट थे, specialists of the team from the Ministry of Health & Family Welfare had been sent from the National Institute of Cholera, Calcutta...

सारी इन्वेस्टीगेशन उन्होंने की, देखभाल की । देखभाल करने के बाद ... (व्यवधान)

श्री संघ प्रिय गौतम : यह कब गई थी ?

श्री बलराम जाखड़ : यह आपको गई है, जनाब, इसी साल में गई है, 1992 में और उन्होंने देखकर के बताया है कि 113 जो है कॉलरा से वहां मौतें हुई हैं, 113 due to outbreak of gastroenteritis, यह उन्होंने वहां देखा क्योंकि पानी का जो है, वह प्रदूषण है और उसके कारण पेट में गडबड हो जाती है । यहां भी, जैसे आपने सुना होगा, पिछले सालों में दिल्ली में जब जल प्रदूषण हुआ तो आपके शाहदरा में और इधर कितने प्रकार से कितनी डैथ यहां भी हुई । उसी प्रकार का एक प्रकोप हुआ है । तो हैल्थ मिनिस्ट्री की एक स्पेशलिस्ट की टीम वहां गई, वहां देखा और जो स्टेट गवर्नमेंट ने वहां से मांगा, कहा कि हमें सहायता दो तो उसके लिए बिल्कुल तत्कालिक तौर पर सहायता देने का प्रबंध करना चाहिए था और किया गया । यहां से टीम गई । देखा और उन्होंने किया सारा का सारा, जितना भी हम कर सकते थे । उन्होंने मांगा हमसे 27 करोड रुपए, मांगा कि 27 करोड रुपया चाहिए, लेकिन आपको पता है कि एक स्कीम बनी हुई है नाइंथ फाइनेंस कमीशन की उसके अलावा फिर किस तरीके से हम उनकी मदद कर सकते थे सैंटर से, जो हम कर सकते थे उसका ब्यौरा मेरे पास है, मैं आपको दूंगा और आगे क्या, कैसे कार्यक्रम से, कौन से उपायों से हम पूरा निराकरण हमेशा के लिए कर सकते थे, वह उपाय भी हमने किए हैं, जिससे कि आइंदा इस प्रकार की वहां गडबड न हो । वह सारा हमने किया है । Annual Calamity Fund of Tripura—Rs. 3 crores· जो त्रिपुरा का तीन करोड था, मैंने सारा का सारा दे दिया । वह दे दिया और entire Central share of Central Calamity Fund has been released in advance, वह भी एडवांस में हमने दे दिया है । फिर, 25 लाख रुपया प्राइम मिनिस्टर फण्ड में से हमने उनको दिया है, 5 करोड़ 27 लाख रुपया जवाहर रोजगार योजना से हमने उनको दिया है जिससे वह काम पूरा कर सके उसमें से और लोगों को कार्य दे सकें, लोग काम में लगें । First, instalment of Central share amounting to Rs. 2 crores or 1 crore 96 lakhs released. इसमें भी हमने दे दिया है । Total resources available including State share of Rs. 49 crores work out to Rs. 245 crores 14 lakhs. यह हमने इसमें किया है और In 1992, an allocation of rice to Tripura has been maintained at 16000 tonnes per month against allocation of 13000 tonnes.

13,000 टन जाया करता था, लेकिन हमने उसको 16,000 टन कर दिया और एक महीने में 22,000 टन तक पहुंचे हैं । एक स्पेशल एडवांस मानसून के लिए 30,000 टन का पहले भेज दिया गया है, जिससे कि वहां और पकड़ हो सके ।

पी०डी०एस० जो है, पब्लिक डिस्ट्रिब्यूशन सिस्टम ठीक सुचारू रूप से काम कर सके, इसका प्रबंध कर दिया गया है । एक जो बहन जी ने कहा, सरला जी ने, कि उनका दुगुना करो जो सप्लाई जा रही है पी० डी०एस० में, उसके लिए मैं कहना चाहता हूं कि Per capita availability of foodgrains in Tripura is 57·92 kgs. against all India average availability of 21·78 kgs. यह हमने उसके लिए किया है क्योंकि वह स्पेशल ध्यान देने की बात है, उसका करना है । सबसे बनी समस्या जो बीमारी फैलाने की है, वह है पानी का जो वहां किया जाए । तो वहां जितने गांव थे, उनमें पीने के पानी का प्रबंध सुचारू रूप से करने के लिए हमने प्रावधान किया । Almost all the 2900 identified problem villages have been provided with drinking water facility. Rest will be covered this year. उसमें क्या किया है ?

Provision of Rs. 7 crores has been made under Minimum Needs Programmes Rs. 3·50 crores under Accelerated Rural Water Supply Programme has been made during the current year. इससे पहले यह किया है, An amount of Rs. 170 crores out of the total of Rs. 220 crores has been released under Minimum Needs Programme at Tripura.

यह सारा उसके लिए इतना पैसा सिर्फ पानी के लिए और करने के लिए है। इसके अलावा और भी है कि किस तरीके से 14 हजार करोड़ रुपए की बजाए 30 हजार करोड़ रुपया रूरल डैवलपमेंट के लिए रखा गया है, वह भी पानी के लिए प्रबंध करने का है। उसमें भी मैं रूरल डैवलपमेंट से कहूंगा कि वह भी वहां पैसा लगाए, जिससे कि आइन्दा गैस्ट्रो इन्ट्राइटिस से मेरे भाइयों को तकलीफ न हो।

The Ministry of Health and Family Welfare have provided medicines worth Rs. 9,75,000.

पौने दस लाख की, जो टीम भेजी गई थी, उसके बाद पौने दस लाख की वहां दवायें भेज दी गई हैं।

The Ministry of Defence have supplied 300 bottles of transfusion fluid.

उस तरीके से उनको कालरा से बचाने के लिए वह भी दिया गया है।

The situation created by the outbreak of gasteroenteritis was brought under control by the State Government immediately.

The State Government undertook the following measures to tackle the situation :

(1) Identification of critical area for distribution of double ration.

(2) Reinforcement of the health institutions.

(3) Sending of mobile medical teams to the affected areas.

(4) Health education campaign.

(5) Improved availability of safe drinking water.

(6) *Ex gratia* payment to the families of deceased.

(7) Distribution of rice and fish as wages to improve the nutrition level.

यह सारा किया है और इसके साथ-साथ सबसे बड़ा प्रकरण यह है कि झूम कल्टिवेशन, जिससे कि गड़बड़ होती है, हम उसका निराकरण करना चाहते हैं और शिक्षा देकर, रिहैबिलिटेशन करके जो किसान झूम कल्टिवेशन में लगे हैं उनको स्थाई रूप से स्थापित करके, अच्छे तरीके से स्थाई खेती करने की हम प्रक्रिया उनको बता रहे हैं और उसके लिए हम पैसा देना चाहते हैं। यह सिर्फ त्रिपुरा के लिए है, सारे फार ईस्टर्न, नार्थ-ईस्ट जो हमारा रीजन है, उसके लिए हम करना चाहते हैं क्योंकि अगर पैदा नहीं करेंगे तो जो बढ़ती हुई आबादी है उसको कहां से देंगे। यह भी हम कर रहे हैं और सारे इस तरह से काम करके इसको ठीक ढंग से निपटा देना चाहते हैं जिससे कि आइंदा कुछ भी गड़बड़ न हो और यह प्रकरण हमने सारे आपके सामने रख दिए हैं। मेरे ख्याल में इसमें ज्यादा मेरे लिए कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। ...
(व्यवधान)

श्री संघ प्रिय गौतम : रोजगार के लिए क्या कर रहे हैं ?

श्री बलराम जाखड़ : रोजगार के लिए भी दिया है, बताया है न मैंने। जवाहर रोजगार योजना में एक्सलरेटिड वाटर सप्लाई थी, उसमें वह सात, साढ़े तीन और दस करोड़ रुपया उसी के लिए दिया है जिससे कि उनके लिए कार्रवाई की जा सके।

[श्री बलराम जाखड़]

मैं देखता हूं कि बहन सरला जी का जो प्रस्ताव है, जैसे सरला जी हैं वैसे ही सरल स्वभाव है उनका । यथा नामः, तथा गुणः होगा । तो मैंने उनकी सारी बातें मान ली हैं, मैं उनकी बात से सहमत भी हूं । अब इसको पास करने की कोई आवश्यकता नहीं है । आप कर लीजिए, हम आपके साथ हैं । इस व्यथा में हम आपके साथ हैं और उसको दूर करने में हमारे सब कार्यक्रम आपके साथ हैं, सहानुभूति भी है ।

श्रीमती सरला महेश्वरी : (पश्चिमी बंगाल) : माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय की शुक्रगुजार हूं और इसके साथ ही साथ मैं सदन के तमाम सदस्यों की भी शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने मेरे प्रस्ताव में उठाए गए विषय की अहमियत को समझते हुए इसमें हिस्सा लिया । मुझे इस बात का भी संतोष है कि सदन के विभिन्न पक्षों के सदस्यों ने मेरे प्रस्ताव की मूल भावना को अपना समर्थन दिया, सिर्फ माननीय कुछेक सदस्यों को छोड़कर जिसमें दुर्भाग्य से त्रिपुरा के भूतपूर्व मुख्य मंत्री, जो हमारे इस सदन के माननीय सदस्य भी हैं—श्री सुधीर रंजन मजूमदार, उन्होंने इसका विरोध किया ।

उपसभाध्यक्ष महोदय, त्रिपुरा में आदिवासियों की मौजूदा स्थिति को लेकर हमारे राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन मैंने यह आशा की थी कि भूख और भूखजनित बीमारियों से पीड़ित आदिवासियों की चिकित्सा के लिए और भूख से मर रहे इन बेसहारा लोगों को सहायता की खातिर मुझे तमाम पक्षों का, सत्ता पक्ष के लोगों की भी समर्थन मिलेगा ।

उपसभाध्यक्ष महोदय, यह एक अत्यंत मानवीय प्रश्न है और मैंने अपने प्रस्ताव को भी बिल्कुल इसी दृष्टिकोण से रखा था । मेरे प्रस्ताव में मैंने तीन मांगें रखी हैं । एक—कि वहां सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए सप्लाई की जा रही वस्तुओं की मात्रा दुगुनी की जाए । दो-व्यापक स्तर पर ग्रामीण रोजगार योजनायें शुरू की जाएं । तीन—भूख से संबंधित रोगों से पीड़ित लोगों के इलाज के लिए पर्याप्त चिकित्सा राहत उपाय शुरू किए जाएं । उपसभाध्यक्ष महोदय इस लिए मैंने यह आशा की थी कि मेरे इस प्रस्ताव को पूरे सदन का समर्थन मिलेगा लेकिन दुर्भाग्य से हमारे सत्ता पक्ष के कुछ लोगों ने मेरे प्रस्ताव की मूल भावना का भी विरोध किया, मुझे आश्चर्य हुआ उपसभाध्यक्ष महोदय, कि इस मानवीय प्रस्ताव को भी वे स्वीकार नहीं पाए । सत्ता पक्ष की ओर से इस बहस में सर्वश्री अहलुवालिया, चौधरी हरि सिंह वी० नारायणसामी, विठ्ठलराव माधवराव जाधव, सुधीर रंजन मजूमदार, श्रीमती सत्या बहिन, मूलचन्द मीणा और बाबा मिश्र जी ने हिस्सा लिया ।

उपसभाध्यक्ष महोदय, सत्ता पक्ष के सभी लोगों ने भले ही कुछ लोगों ने मेरे प्रस्ताव की मूल भावना का समर्थन किया लेकिन वे तमाम सदस्य इस बात पर एकमत थे कि मेरा यह प्रस्ताव राजनीतिक उद्देश्यों से प्रेरित है । उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या राजनीति करना जुर्म है क्या हमारी राजनीति इतनी ही सम्वेदन शून्य और मानवीय सरोकारों से परे हो गई है कि उसके तहत हम कोई मानवीय समस्या उठा नहीं सकते । उपसभाध्यक्ष महोदय, अगर यही सच है तो फिर हमारा इस सदन में बैठने का औचित्य ही क्या है और इस पूरे तामझाम का ही औचित्य क्या है? उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहूंगी कि परहेज राजनीति से नहीं बल्कि मानवद्रोही राजनीति से करना चाहिये । उस राजनीति से करना चाहिये जो शोषण और जुल्म पर टिकी हुई व्यवस्था का समथन करती है ।

उपसभाध्यक्ष महोदय, जहां तक हमारा सवाल है, मुझे यह कहते हुये गर्व है कि मैं जिस राजनीति से संबद्ध हूं, वह राजनीति आम जनता के दुख और सुख के साथ संबद्ध राजनीति है। हमारी राजनीति शोषित और उत्पीड़ित जनता के संघर्षों से प्रतिबद्ध राजनीति है और उनके हित में कोई बात उठाने पर यदि हम पर यह आरोप लगाया जाता है कि हम राजनीति से प्रेरित हैं, तो उपसभाध्यक्ष महोदय, अगर मैंने यह गुनाह किया है तो मैं सहर्ष स्वीकार करते हुये यह कहना चाहूंगी :

"हां हम ही मुजरिम हैं,
चढ़वादो हमें तुम दार पर,
हमने छेड़ी जिंदगी के दर्द
रूखसारों की बात।"

कुछ माननीय सदस्य : एक बार और।

श्रीमती सरला माहेश्वरी : तो आप इनका समर्थन कर दीजिये। **(व्यवधान)**

उपसभाध्यक्ष महोदय, अगर हमारे सत्ता पक्ष के मित्रों ने सिर्फ मुहावरे के तौर पर यह बताने के लिये कि मैंने बद-इरादों से प्रेरित होकर यह प्रस्ताव पेश किया है, मुझ पर राजनीति से प्रेरित होने का अभियोग लगाया है, तो इस पर मेरा सिर्फ यही कहना है कि मेरे इन कथित बद-इरादों के जवाब में हमारे इन साथियों ने जो दलीलें दी हैं, उन तमाम दलीलों को अगर आप गहराई से देखें तो आप पायेंगे कि जो अभियोग वह मेरे पर लगा रहे हैं वह अभियोग उन पर कितना सही उतरता है। उपसभाध्यक्ष महोदय, सत्ता पक्ष के लोगों ने जो दलीलें दी हैं, मैं उन पर आती हूं।

सबसे पहले श्री अहलुवालिया जी के वक्तव्य को ही लिया जाय।.. **(व्यवधान)** उन्होंने अपने भाषण में इस बात पर एतराज किया है मैं त्रिपुरा में अकाल, अभाव, भूख और भुखमरी की घटनाओं पर इतना भावुक क्यों हो गई। उनका कहना था कि जहां आदमी होगा उसका पेट होगा, वहां भूख होगी, भुखमरी होगी। उन्हीं के शब्दों को यहां उद्धृत करना चाहूंगी:

"जब से इंसान पैदा हुआ है मेरा ख्याल है कि भुखमरी भी उस वक्त से इंसान के साथ जुड़ी हुई है। जब से इंसान के शरीर के साथ पेट जुड़ा हुआ है, भूख जुड़ी हुई है और जिन्दगी में अभाव भी तब से जुड़े रहे हैं।"

इसलिये उनका कहना था कि इन अभावों और दुखों को मैंने राजनीति का विषय क्यों बनाया ? अब, उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहती हूं कि क्या इस तर्क का भी कोई जवाब हो सकता है। आप ही बताइये कि भला हम राजनीति क्यों करते हैं। राजनीति का उद्देश्य क्या है ? मेरी समझ में तो राजनीति का यही उद्देश्य है कि हम लोगों की जिन्दगी से दुखों को, अभावों को दूर करके उनकी जिन्दगी में सुख और समृद्धि लायें।

श्री संघ प्रिय गौतम : वह तो सामाजिक सेवा है।

श्रीमती सरला माहेश्वरी : इसके इतर अगर राजनीति का कोई उद्देश्य है तो वह शायद हमारे कांग्रेस के लोग ही जानते होंगे। यदि बोफोर्स, शेयर धांधली और सत्ता की दलाली ही राजनीति है तो यह राजनीति हमारे सत्ता पक्ष के लोगों को ही मुबारक।

उपसभाध्यक्ष महोदय, अहलुवालिया जी समेत सत्ता पक्ष के सभी लोगों ने त्रिपुरा में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के शासन काल को उठाया है। सबने यह सवाल उठाया है कि वहां जब आपकी पार्टी थी तब आपने क्या किया। हमारे भूतपूर्व मुख्यमंत्री सुधीर रंजन मजूमदार जी ने भी यह सवाल उठाया। अफसोस हुआ मुझे उनके भाषण को सुनकर कि उन्होंने खुद अपने शासन काल में क्या किया, यह तो नहीं बताया लेकिन त्रिपुरा में इतने बरसों तक मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के शासन काल में क्या हुआ, इसको भी बताने की अपनी

[श्रीमती सरला माहेश्वरी]

तरफ से उन्होंने कोई कोई कोशिश नहीं की । इसलिये मेरा यह फर्ज बनता है कि जो अहलुवालिया जी ने कहा है कि सरकारें आती और जाती रहेंगी लेकिन इन गरीबों का फैसला कौन करेगा, मैं इस सवाल को बिल्कुल छोड़ना नहीं चाहती । नहीं इस सवाल से कतराना चाहती हूं ।

महोदय, त्रिपुरा में वाम मोर्चा सरकार के दस वर्षों में वहां की गरीब, जनता, अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों के लिये जो कार्य किये गये और हमारे राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिये जो कुछ किया गया, उस पर हमें हमेशा गौरव रहेगा । यहां मैं संक्षेप में हमारी वाम मोर्चा सरकार के शासन में जो कुछ किया गया, उसकी छोटी सी तफसील देना चाहूंगी । महोदय, 5 जनवरी, 1978 को त्रिपुरा में पहली बार वाम मोर्चा सरकार बनी थी । उस सरकार को विरासत में क्या मिला? उसे विरासत में मिली एक पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्था, जर्जर आर्थिक स्थिति, साम्राज्यवाद और अलगाववादियों के षड्यंत्र, त्रिपुरा के उत्पीड़ित आदिवासियों में अलगाव की तीव्र भावना तथा आदिवासी और बंगाली समाज के भीतर लगातार बढ़ती जा रही कटुता और विद्वेष । त्रिपुरा में उद्योगों का तो नामोनिशान नहीं था । कृषि की स्थिति भी काफी पिछड़ी हुई थी । इस एक तथ्य से ही उस काल का पूरा चित्र उभरकर सामने आ जायेगा कि उस समय उस छोटे से राज्य की 82 फीसदी जनता गरीबी की रेखा के नीचे थी । त्रिपुरा पूरी तरह उजाड़ था । अराजकता का बोलबाला था । योजनाबद्ध विकास का कोई नामोनिशान नहीं था । जिस दिन वाम मोर्चा सरकार बनी, उसके दूसरे दिन ही साम्राज्यवादियों और अलगाववादियों ने उसके खिलाफ एक के बाद एक षडयंत्र शुरू कर दिये । त्रिपुरा में संचार की कठिनाई के कारण ।...(**व्यवधान**)

श्री संघ प्रिय गौतम : उपाध्यक्ष महोदय, यह बातें विषय से बाहर हैं ।

SHRI SUDHIR RANJAN MAJUMDAR : She is giving a wrong figure. The people who were below the poverty-line were 51 per cent of the population when they came to power and this figure went up to 82 per cent when they were in power.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SATYA PRAKASH MALAVIYA) : You continue.

श्रीमती सरला माहेश्वरी : उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं जो कहना चाह रही थी, हमारे माननीय सदस्यों ने कहा कि यह विषयांतर है मैं विषयांतर नहीं कर रही हूं, मैं हमारे सत्ता पक्ष के लोगों को जो कि आज भी अंधेरे में हैं या अंधेरे का बहाना कर रहे हैं, मैं उनकी आंखों में थोड़ी रोशनी की किरण पहुंचाना चाहती हूं ।

उपसभाध्यक्ष महोदय, वाम मोर्चा सरकार पूरे दस वर्षों तक त्रिपुरा को रेल लाइन से जोड़ने की मांग केन्द्रीय सरकार से करती रही । इसके लिए उसने कितने ही आंदोलन भी किए लेकिन केन्द्रीय सरकार की उदासीनता का आलम यह रहा कि इन दस वर्षों में धर्मनगर से लेकर पेचारखान तक केवल 2 किलोमीटर लाइन बनाई गई ।

रेल मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० मल्लिकार्जुनन) : धर्मनगर से कुमारघाट 32 किलोमीटर है । वह लाइन बनाई गई है ।

श्रीमती सरला माहेश्वरी : आप मुझे तथ्य भेजिएगा, मैं देख लूंगी । हमारे पास जो तथ्य है वह यह है कि पिछले 10 वर्षों में केवल दो किलोमीटर रेल लाइन बनी है । इन तमाम प्रतिकूलताओं के बीच वाम मोर्चा सरकार ने राज्य के गरीबों, खास तौर से अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लोगों के जीवन में सुधार लाने के लिए कृषि में सुधार को पहली प्राथमिकता दी । जो त्रिपुरा के लोग पंचायतों के गठन के बारे में बिल्कुल अनभिज्ञ थे, वहां कानून बनाकर दो-दो बार पंचायतों के चुनाव कराए गए ।

गांवों से निहित स्वार्थों की जकड़बंदी को खत्म किया गया । पंचायतों ने कृषि के क्षेत्र में अभूतपूर्व काम किया । सच्चा भूमि सुधार लागू किया गया । 70000 भूमिहीनों को जमीन दी गई, 50000 गृहहीन लोगों को आवास के लिए जमीन दी गई । उस छोटे से राज्य में 1929 एकड़ अतिरिक्त जमीन की शिनाख्त की गई । इसमें से 1529 एकड़ जमीन 1310 भूमिहीनों में, 310 अनुसूचित जातियों के लोगों और 235 अनुसूचित जनजाति के लोगों में बांटी गई । जिस त्रिपुरा में कृषि की स्थिति बिल्कुल पिछड़ी हुई थी, जहां कृषि में सुधार के लिए एक भी रिसर्च सेंटर नहीं था, वहां वाम मोर्चा सरकार ने एक नहीं कई ऐसे सेंटर स्थापित किए । अरुंधती नगर में रिसर्च और डिमांस्ट्रेशन सेंटर, लीम्बूछेड़ा में रिसर्च इंस्टीट्यूट खोवाई में ऐग्रो साइंस इंस्टीट्यूट बनाया गया । दक्षिणी जिले में एक इंस्टीट्यूट खोला गया । पश्चिमी जिले में इंप्रूव्ड सीड मल्टीप्लिकेशन सेंटर बनाया गया ।

महोदय, जिस प्रदेश में रासायनिक खाद की चेतना हीं नहीं थी वहां इसको बढ़ा दिया गया और इसके परिणाम-स्वरूप 1976–77 में जहां 866 टन रासायनिक खाद आता था वहां 1985–86 में 4800 टन पहुंच गया ।

उपसभाध्यक्ष (श्री सत्य प्रकाश मालवीय) : आप थोड़ा कम करेंगी ?....

श्रीमती सरला माहेश्वरी : मैं चाहती थी कि हमारे माननीय सदस्यों को जानकारी हो...

माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, इस समय वाम मोर्चा सरकार के काल में उद्योगों के क्षेत्र में तमाम काम किया गया । 1982–83 में त्रिपुरा औद्योगिक विकास निगम का गठन किया गया है । इसी शासन के दौरान राज्य में करीब 50 नए चाय बागान बने । इन चाय बागानों को लेकर 1980 में चाय विकास निगम का गठन किया गया है । हस्त-शिल्प के क्षेत्र में वहां पर बेमिसाल काम किया गया है ।

जहां तक शिक्षा और संस्कृति का संबंध है, वाम मोर्चा का शासनकाल त्रिपुरा में नव-जागरण का काल है । त्रिपुरा ही वह राज्य था जहां वाम मोर्चा सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि स्वशासी जिला परिषद् का गठन करना है । सबसे पहले संविधान की 7वीं सूची के अंतर्गत 1982 में त्रिपुरा के आदिवासी क्षेत्रों के लिए स्वशासी जिला परिषद् का गठन किया गया है और इसके बाद 1985 में और ज्यादा अधिकारों से संपन्न करके संविधान की छठी अनुसूची के अंतर्गत स्वशासी जिले का गठन किया गया है । लगभग 700 स्क्वायर किलोमीटर और साढ़े 6 लाख लोग वहां बसते है जिनमें से साढ़े चार लाख आदिवासी है । इस स्वशासी जिले में सच्चे जनतंत्र की स्थापना करके हमारे देश में जुड़ाव की भावना को बल पहुंचाया गया और राष्ट्रीय एकता और अखंडता की भावनाओं को बल पहुंचाया गया ।

इस प्रकार से उपसभाध्यक्ष महोदय, जहां तक उपलब्धियों का सवाल है, त्रिपुरा में 10 वर्षों में वाम मोर्चा सरकार का शासन ऐसा था जिसके चलते आज स्थिति यह है कि त्रिपुरा में कांग्रेस और टी०यू०सी०जे० की गठजोड़ सरकार को फासीवादी आतंक वहां पर चला रहे है । इसके बावजूद त्रिपुरा में सी०पी०एम० को वहां की जनता से काटा नहीं जा सकता है, इस बात में मुझे कोई शक नहीं है, कोई संदेह नहीं है । सरकार के बदलने का मतलब जनता से जाना नहीं है...

उपसभाध्यक्ष (श्री सत्य प्रकाश मालवीय) : सारे प्वाइंट तो आप कह चुकी है। अब खत्म करिये ।

श्रीमती सरला माहेश्वरी : मैं खत्म ही कर रही हूं । सिर्फ एक प्रश्न उठाना चाहती हूं जो बहुत ही ज्वलंत प्रश्न है ।

[श्रीमती सरला माहेश्वरी]

त्रिपुरा में हमारे अहलुवालिया साहब और तमाम सत्ता पक्ष के लोगों ने इस प्रश्न को बार-बार उठाया कि वहां खाद्यान्न की स्मगलिंग होती है । मैं यह कहना चाहती हूं कि इसके लिए कौन जिम्मेदार है ? इस भ्रष्टाचार के लिए कौन जिम्मेदार है ? आपको आश्चर्य होगा कि असम के सिलचर में एक गोदाम है जिस गोदाम में त्रिपुरा और मिजोरम का खाद्यान्न इकट्ठा किया जाता है । अखबारों में आया है कि पिछले कई वर्षों से इस गोदाम से खाद्यान्न की चोरी होती है, लाखों टन खाद्यान्न चोरी हो रहा है । इस गोदाम से लाखों टन खाद्यान्न बंगलादेश में जा रहा है और घपले में किस का नाम आ रहा है ? इस घपले में नाम आ रहा है कांग्रेस (इ) के एक मंत्री का ।

श्री एस. एस. अहलुवालिया (बिहार) : उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं प्वाइंट आफ इन्फरमेशन में यह इन्फरमेशन देना चाहता हूं कि परसों ही सी.बी.आई. ने अपनी प्रेस रिलीज में कहा है कि यह जो अखबारों में छपा है हमारे नाम से कि सी.बी.आई. ने इंक्वायरी की है, सी.बी.आई. ने रेड़ की है और उसमें कांग्रेस के मंत्री या कांग्रेस के कार्यकर्ता का नाम है यह गलत है । उन्होंने कहा कि न तो हमने किसी की इंक्वायरी की है और न हमने कोई रेड़ की है यह अखबारों में जो स्टोरी छप रही है । यह निराधार है । सी.बी.आई. प्रेस रिलीज में यह कहा गया है ।

SHRI SUNIL BASU RAY : This is the reason why the Head of the CBI had to seek voluntary retirement.

उपसभाध्यक्ष (श्री सत्य प्रकाश मालवीय) : अब आप समाप्त करिये ।

श्रीमती सरला माहेश्वरी : मैं समाप्त ही कर रही हूं । हमारे सत्ता पक्ष के लोग, जो भ्रष्टाचार और स्मगलिंग वहां हो रही है क्या उसकी तहकीकात करेंगे या सी.बी.आई. का स्पष्टीकरण उनके लिए काफी है ? क्या उनका दायित्व नहीं बनता कि एक के बाद एक जो घोटाले हो रहे है और जो सरकार एक घोटाले की सरकार बन गई है क्या तमाम लोगों का यह दायित्व नहीं बनता जो उच्च आसन्न पर लोग बैठे हैं उनका दायित्व नहीं बनता कि इसकी छानबीन करायें क्योंकि लगातार मंत्रियों पर आरोप लग रहे हैं और हमारे एक माननीय सदस्य सिर्फ सी.बी.आई. का हवाला देकर इस बात से अपनी कन्नी काट लेना चाहते हैं । यह बड़े शर्म की बात है । त्रिपुरा के लोग भूखों मर रहे हैं । वहां खाद्यान्न के घोटाले में एक का नाम आता है, केन्द्रीय मंत्री का नाम आता है, इससे ज्यादा शर्म की बात कुछ नहीं हो सकती । (व्यवधान) ।

उपसभाध्यक्ष (श्री सत्य प्रकाश मालवीय) : आप कृपया समाप्त करिये

मानव संसाधन विकास (युवा कार्य और खेल विभाग) मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय (महिला और बाल विकास विभाग) में राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार (कुमारी ममता बनर्जी) : सब झूठ है । (व्यवधान)

श्री विठ्ठलराव माधवराव जाधव : उपसभाध्यक्ष महोदय, यह रेजोलूशन क्या है और बोल क्या रही है ? यह किस का जवाब दे रही है ? (व्यवधान)

SHRI SUNIL BASU RAY : You invited the discussion. You are accusing her of bringing in politics.

उपसभाध्यक्ष (श्री सत्य प्रकाश मालवीय) : अब आप समाप्त करिये ।

श्रीमती सरला माहेश्वरी : मैं आपका संरक्षण चाहती हूं । अगर सत्ता पक्ष के लोग इस तरह से कटाक्ष करते रहे तो इनका जवाब देना मेरा दायित्व बन जाता है । मैं मंत्री महोदय की जानकारी में लाना चाहती हूं कि पिछले तीन वर्षों

में त्रिपुरा में किस तरह से खाद्यान्न की आपूर्त्ति की गई । 1989–90 में 66,614 टन चावल भेजा गया । 1990–91 में 53,400 टन और 1991–92 में 5,249 टन भेजा गया । मैं चाहूंगी मंत्री महोदय अगर मेरे तथ्य गलत है तो उनको ठीक कर देंगे । आज वहां पर अकाल और भूख से लोग मर रहे है और वहां पर लगातार अनाज का कोटा कम हो रहा है । इसलिए मैं मंत्री महोदय से अपील करना चाहूंगी कि वह एक बार फिर अपने तमाम पक्ष के लोगों को इस बात के लिए तैयार करें कि यह जो मेरा प्रस्ताव है इसमें माननीय सवाल है इसको मान लें । अगर हमारे सत्ता पक्ष के लोगों में थोडी भी संवेदना बनी हुई है, इंसानियत बची हुई है तो मैं चाहूंगी कि हमारे इस सदन की गरिमा की रक्षा करते हुए इस मानवीय प्रस्ताव को पास करें । इन्हीं शब्दों के साथ मैं समाप्त करती हूं ।

उपसभाध्यक्ष (श्री सत्य प्रकाश मालवीय) : आप अपना प्रस्ताव वापस लेती है या आपके प्रस्ताव पर मत कराया जाए ।

श्री सिकन्दर बख्त : मंत्री जी कुछ आश्वासन दे दें ...

†[شری سکندر بخت : منتری جی کچھ آشواسن دے دیں]

श्रीमती सरला माहेश्वरी : मैं चाहूंगी मंत्री जी कुछ ठोस आवाज निकालें जो हमारे त्रिपुरा के आदिवासी लोगों तक पहुंचे । मैं मंत्री महोदय से आश्वासन चाहती हूं ।

श्री बलराम जाखड़ : उपसभाध्यक्ष जी, जैसा अभी श्री सिकन्दर बख्त जी ने कहा, मैं तो शुरू से ही आपकी बात कह रहा हूं । उसके बाद भी आप नहीं समझ रही है । मैंने कहा कि जो आपके दिल की व्यथा है वही व्यथा यहां भी है । हम ऐसा कभी नहीं होने देंगे । हमारी चेष्टा यही होगी कि जो कुछ करना है, ठोक ढंग से हो, उनके लिए जो गड़बड़ियां हैं उनका निराकरण करना है और हम करके छोड़ेंगे । इसलिए आप अपने प्रस्ताव को वापस ले लें ।

श्रीमती सरला माहेश्वरी : उपसभाध्यक्ष जी, मैं चाहूंगी कि अगर मंत्री महोदय इस बात की तहकीकात कर दें और जल्दी से जल्दी फौरन वहां पर अपना राहत का कार्यक्रम शुरू कर दें तो मैं आशा करती हूं कि लोगों को राहत पहुंचेगी । इसके साथ ही मैं अपने प्रस्ताव को वापस लेती हूं ।

The resolution was, by leave, withdrawn

RESOLUTION REGARDING REDUCTION IN THE MINIMUM AGE FOR ELECTION TO LEGISLATIVE BODIES

श्री सुरेश पचौरी (मध्य प्रदेश) : माननीय उपसभाध्यक्ष जी, मेरे नाम से जो संकल्प है उसको मैं इस सदन के विचारार्थ प्रस्तुत करता हूं और इस आशा और उपेक्षा के साथ कि इस सदन के सभी सम्मानीय सदस्य मेरे द्वारा उठाई गई बातों को दृष्टिगत रखते हुए जो मेरी भावना इस संकल्प में है उसका समर्थन करेंगे ।

मैं निम्नलिखित संकल्प उपस्थित करता हूं –

"इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि यद्यपि देश के युवाओं को 1988 में एक संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष करके लोकतांत्रिक प्रणाली का एक सबसे महत्वपूर्ण अधिकार अर्थात् "हाउस आफ दि पीपुल" (लोक सभा) और राज्य विधान सभाओं के चुनावों में मतदान करने का अधिकार दिया गया है, तथापि संसद और राज्य विधान मंडलों के लिए चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु में अब तक परिवर्तन नहीं किया गया है यह सभा सरकार से "कौंसिल आफ स्टेट्स" (राज्य सभा) और विधान

† [ ] Transliteration in Arabic Script.